राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

कार्यालय ऑफिस

क्रांति समय दैनिक समाचार में
प्रेसनोट, नोटिस, वेपार संबंधित संपर्क करें
पता:- एस.टी.पी.आई-सुरत-395023
संपर्क नं.-7490923915
ईमेल:-info.krantisamay@gmail.com

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई, उत्तरप्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्यप्रदेश, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा में प्रकाशित

सुरत-गुजरात, संस्करण सोमवार 01 दिसंबर 2025 वर्ष-8,अंक-274 पृष्ठ-08 मूल्य-01 रूपये

Website : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

पहला कॉलम

श्रीलंका में दितवाह ने मचाई तबाही, 150 की मौत!

भारत ने शुरु किया ऑपरेशन सागर बंधु

कोलंबो

चक्रवात दितवाह ने श्रीलंका को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। तेज हवाओं, मूसलाधार बारिश और बाढ़-भूस्खलन से पूरे द्वीप राष्ट्र में भयंकर तबाही हुई है। इस विपदा में 2 लाख से अधिक लोग (करीब 61,000 परिवारों से) प्रभावित हुए हैं। पूरे देश में बाढ़ का कहर है, खासकर राजधानी कोलंबो और पूर्वी तटों पर। श्रीलंका के आपदा प्रबंधन केंद्र (डीएमसी) के अनुसार, रविवार की सुबह तक कम से कम 150 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 130 अन्य अभी भी लापता हैं। वहीं 300 भारतीय फंसे हुए हैं। यह आंकड़े पिछले कुछ दिनों की लगातार बढ़ती तबाही को दर्शाते हैं, जहां शुरुआत में 40-50 मौतों की खबरें थीं, जो अब 150 तक पहुंच गई हैं।

केलानी नदी शनिवार शाम को उफान पर आ गई, जिससे सैकड़ों लोग अस्थायी आश्रयों में स्थानांतरित हो गए। उत्तरी क्षेत्रों में अभी भी हल्की बारिश जारी है, लेकिन अधिकांश जगहों पर वर्षा थम चुकी है। डीएमसी ने बताया कि चक्रवात के अवशेषों के कारण बिजली कटौती, सड़कें बंद और रेल सेवाएं ठप हो गई हैं। स्कूलों और कार्यालयों को भी बंद रखा गया है। चक्रवात दितवाह 24 नवंबर से श्रीलंका के आसपास सक्रिय हो गया था। यह धीरे-धीरे उत्तर-पश्चिम दिशा में बढ़ा और 26 नवंबर (बुधवार) को पूर्वी तट पर लैंडफॉल कर गया। उसके बाद 28 नवंबर (शुक्रवार) को तेज हवाओं (50-70 किमी/घंटा) के साथ भारी बारिश शुरू हो गई, जो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची- कुछ इलाकों में 24 घंटों में 300 मिमी से अधिक। इससे भूस्खलन और बाढ़ ने पूरे द्वीप को घेर लिया।सबसे ज्यादा तबाही पूर्वी और मध्य पहाड़ी इलाकों (जैसे बदुल्ला, नुवारा एलिया) में हुई। कोलंबो की सड़कें जलमग्न हो गईं, जहां लोग नावों या अस्थायी राफ्ट पर घूमने को मजबूर हैं। 600 से अधिक घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं, और हजारों बेघर हो गए हैं। मौतों में महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लापता लोगों में कई वे हैं जो भूस्खलन में फंस गए। डीएमसी प्रमुख प्रदीप कोटुवेगोदा ने कहा- चक्रवात अब भारत की ओर जा रहा हैं।

भारत ने 21 टन राहत सामग्री भेजी

भारत ने एक बार फिर नेबरहुड फर्स्ट नीति को साकार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ट्वीट कर श्रीलंका के लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की। भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तत्काल राहत सामग्री और मानवीय सहायता भेजी है। एनडीआरएफ की दो टीमों में 80 जवान (जिनमें 4 महिला सदस्य और 4 स्निफर डॉग शामिल) को शनिवार को ही हिंडन एयर बेस से कोलंबो भेजा गया। वे विशेष उपकरणों के साथ बचाव कार्य में जुटे हैं। भारतीय वायुसेना ने सी-130 और आईएल-76 विमानों से 21 टन राहत सामग्री (खाने-पीने का सामान, दवाइयां, कंबल आदि) और 8 टन विशेष उपकरण एयरलिफ्ट किए। विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने भी ट्वीट कर सहयोग की पुष्टि की।

उत्तराखंड में आया 3.7 का भूकंप, डर से लोग मैदान की तरफ भागे, कोई नुकसान नहीं

चमोली उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार सुबह हल्के भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.7 मापी गई। अचानक धरती हिलने से घबराए लोग घरों से बाहर आ गए। हालांकि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है। राष्ट्रीय भूकंप केंद्र के मुताबिक इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 3.7 दर्ज की गई जिसे हल्की तीव्रता वाला भूकंप माना जाता है। यह घटना सुबह 10:27 बजे की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय लोगों ने बताया कि भूकंप के झटके कुछ सेकंड तक ही महसूस किए गए लेकिन डर से लोग घरों और इमारतों से बाहर खुले मैदान की ओर भागे। जिला प्रशासन ने घटना के तुरंत बाद अलर्ट जारी कर किया और किसी भी संभावित स्थिति से निपटने राहत टीमों को तैयार रहने का निर्देश दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हल्के भूकंप से कोई जान-माल की हानि नहीं हुई है और संपत्ति को भी नुकसान पहुंचने की सूचना नहीं है। विशेषज्ञ इस क्षेत्र में भूगर्भीय गतिविधियों पर लगातार नज़र रख रहे हैं।

लंबे समय तक पड़ने वाले सूखे ने सिंधु घाटी सभ्यता का किया विनाश

पलायन पानी, खाने की कमी से हुई मौतें, सभ्यता के पतन का कारण बनीं

नई दिल्ली प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता अपनी उन्नत शहरी संरचना, जल निकासी प्रणाली और धातु के इस्तेमाल के लिए जानी जाती थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और राखीगढ़ी जैसे स्थल इसकी ऐतिहासिक पहचान हैं। लंबे समय से इतिहासकार और पुरातत्वविद यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इतनी उन्नत सभ्यता अचानक गायब क्यों हो गई। अब आईआईटी गांधीनगर के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि लंबे समय तक पड़ने वाले सूखे ने इस सभ्यता को नष्ट कर दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक शोध का नेतृत्व करने वाले शोधकर्ता ने बताया कि सिंधु घाटी के लोग सिंधु नदी के पानी पर निर्भर थे और खेती उनकी प्रमुख आजीविका थी। रिसर्च के मुताबिक मौसम और मॉनसून में बदलाव से बारिश में 10 से 20 फीसदी की कमी आई और औसत तापमान 0.5 डिग्री बढ़ गया। 85 सालों में कम से कम चार गंभीर सूखे पड़े, जिनमें एक तो 164 सालों तक चला। इन सूखों के चलते नदियां और झीलें सूखने लगीं। पानी की कमी ने कृषि को प्रभावित किया, जिससे लोग गेहूं और अन्य अनाज छोड़कर दूसरी फसलों की खेती करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। अध्ययन से पता चला कि उत्तरी अटलांटिक में तापमान घटने से मॉनसून कमजोर हुआ और प्रशांत व हिंद महासागर के बढ़ते तापमान ने भी बारिश को प्रभावित किया। धीरे-धीरे सिंधु घाटी के बड़े शहर छोटे-छोटे कबीलों में बंट गए। पानी की कमी, कृषि की असफलता और खाद्यान्न की कमी ने इस सभ्यता का पतन कर दिया।

चुनाव आयोग ने एसआईआर प्रोग्राम की समय सीमा बढ़ाई, अब 14 फरवरी तक होगा पुनरीक्षण

नई दिल्ली चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रोग्राम की समय सीमा एक सप्ताह के लिए बढ़ाकर 14 फरवरी तक कर दी है। यह निर्णय ऐसे समय में लिया गया है जबकि संसद का शीतकालीन सत्र सोमवार 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। संसद में एसआईआर को लेकर हंगामा होने की संभावना लगातार जताई जा रही है। इससे पहले चुनाव आयोग ने अपने तीन पत्रों के आदेश में बताया कि पोल अधिकारियों को वोटरों की ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया गया है। पहले यह प्रक्रिया 4 दिसंबर तक पूरी होनी थी और ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर को जारी होनी थी। अब वोटर लिस्ट की गिनती 11 दिसंबर तक खत्म होगी, जबिक ड्राफ्ट लिस्ट 16 दिसंबर को जारी होगी और फाइनल वोटर लिस्ट 14 फरवरी 2026 को पब्लिश की जाएगी। समय सीमा बढ़ाने का कारण बीएलओ पर बढ़ते दबाव को बताया जा रहा है। विपक्षी पार्टियों, खासकर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात कर एसआईआर प्रक्रिया को रीशेड्यूल करने का आग्रह किया था। उनका कहना था कि यह काम घर-घर जाकर पूरा किया जा रहा है और अधिकारियों पर बहुत तंग शेड्यूल में अत्यधिक दबाव है। रिपोर्ट्स में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से अनेक बीएलओ की आत्महत्या की खबरें भी सामने आई हैं। चुनाव आयोग ने अनुमान लगाया है कि एसआईआर एक्सरसाइज के तहत ड्राफ्ट लिस्ट से लगभग 35 लाख वोटर्स हटाए जा सकते हैं। इसमें 18.70 लाख मृतक वोटर्स, डुप्लीकेट वोटर्स, ऐसे वोटर्स जिनका पता नहीं चल पा रहा है और वे लोग शामिल हैं जो स्थायी रूप से किसी अन्य राज्य में चले गए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य वोटर लिस्ट को सटीक और विश्वसनीय बनाना है, ताकि अगले साल होने वाले चुनावों में गड़बड़ी की संभावना कम हो। आयोग ने अधिकारियों और जनता से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया में सहयोग दें और आवश्यक दस्तावेज समय पर जमा करें।

पाकिस्तान को दिया गच्चा.... .....भारत और अफगानिस्तान ने

बायपास मार्ग से शुरु कर दिया कारोबार

नई दिल्ली

भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की जा रही कार्गो फ्लाइट्स से पाकिस्तान की शाहबाज सरकार को मिर्ची लग सकती है।

दरअसल पाकिस्तान द्वारा बार-बार सीमा बंद करने के कारण अफगानिस्तान के व्यापार को हो रहे नुकसान के जवाब में बायपास के तौर पर काम करेंगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच सीधे कार्गो फ्लाइट्स (एयर फ्रेट कॉरिडोर) की शुरुआत की जा रही है। पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाना और अफगानिस्तान की पाकिस्तान पर निर्भरता कम करना। यह सहमति अफगान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री अल-हाज नूरुद्दीन अजीजी की भारत यात्रा के दौरान बनी। काबुल-दिल्ली और काबुल-अमृतसर सेक्टरों पर एयर फ्रेट कॉरिडोर सक्रिय कर दिए गए हैं। भारत की ओर से सभी औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, और फ्लाइट्स बहुत जल्द शुरू होंगी, अब केवल अफगान अधिकारियों की तरफ से दस्तावेज़ों का काम बाकी है। हाल के सालों में पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच दुश्मनी बढ़ी है, जिसके कारण पाकिस्तान बार-बार बॉर्डर क्रॉसिंग (जैसे तोरखम और चमन) बंद कर देता है और आवागमन सीमित करता है। सीमा बंद होने से अफगान निर्यात ठप पड़ गया, हजारों व्यापारी फंसे, और किसानों/निर्यातकों को 100 मिलियन डॉलर से अधिक का नुकसान हुआ। इसके अलावा जल्दी खराब होने वाले सामान (फल, मेवे, जड़ी-बूटियाँ) ट्रकों में रुकने से सड़ गए, जिससे कृषि व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। लेकिन अब कार्गो फ्लाइट्स से अफगान उत्पाद कुछ घंटों में भारत के बाजारों तक पहुँच सकते हैं, जबकि ज़मीनी रास्ते से हफ्तों का समय लगता था।

आज के भारतीय तो अपनी मातृभाषा के शब्द भी नहीं जानते: मोहन भागवत

नागपुर

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रमुख मोहन भागवत ने मातृभाषाओं के उपयोग को लेकर गंभीर चिंता जताई है। नागपुर में एक पुस्तक विमोचन के अवसर पर बोलते हुए भागवत ने कहा, कि आज बहुत से भारतीय अपनी मातृभाषा के शब्द भी नहीं जानते हैं और अंग्रेजी के मिश्रण से संवाद करते हैं। उनका कहना है कि इस प्रकार हमारी भाषायी विरासत का क्षय हो रहा है।

यहां भागवत ने कहा, एक समय था जब रोजमर्रा की भाषा में संस्कृत का प्रयोग आम था। अब हाल यह है कि अमेरिका के प्रोफेसर हमें संस्कृत पढ़ाते हैं। उन्होंने मातृभाषा के अभ्यास और ज्ञान पर जोर देते हुए कहा कि बच्चों को अपनी भाषा की समझ होनी चाहिए। भागवत ने उदाहरण देते हुए कहा कि संत ज्ञानेश्वर ने भगवद्गीता को मराठी में प्रचारित किया, जिससे भाषा और संस्कृति की गहराई समझ में आती है। आरएसएस प्रमुख ने अंग्रेजी शब्दों की सीमा पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी भावनाओं और सांस्कृतिक अर्थों की गहराई को पकड़ नहीं पाती। उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि कल्पवृक्ष के लिए अंग्रेजी में कई शब्द हैं, लेकिन कोई भी इसका वास्तविक अर्थ नहीं बता सकता। उनका कहना है कि विदेशी भाषाएं हमारी संस्कृति की पूर्ण गहराई तक नहीं पहुंच सकतीं। इसी के साथ भागवत ने मातृभाषाओं को सीखने और मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते, पाक सरकार की चुप्पी चिंताजनक

इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर फैल रही अफवाहों पर शशि थरूर ने जताई चिंता

नई दिल्ली

पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक इमरान खान के स्वास्थ्य को लेकर फैल रही अफवाहों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चिंता जताई है। उन्होंने इस मुद्दे पर पाकिस्तानी सरकार की चुप्पी को चिंता जनक बताया और कहा कि आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते। साथ ही उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, लेकिन यहां एक इंसान की जिंदगी दांव पर है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक थरुर ने इमरान खान के स्वास्थ्य की अफवाहों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करना हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरह की खामोशी है।

वह निश्चित रूप से चिंता की बात है। कई लोग दावा कर रहे हैं कि सबसे बुरी स्थिति आ चुकी है, लेकिन पाकिस्तान सरकार और वहां के अधिकारियों की ओर से कोई बयान नहीं आया है। ये चुप्पी अच्छी नहीं है।

उन्होंने इमरान खान के बेटे के हालिया बयान का जिक्र करते हुए कहा कि उनके बेटे ने कहा है कि वह अपने पिता के जिंदा होने का सबूत चाहते हैं। अभी तक किसी ने भी ये सबूत नहीं दिया है कि उनके पिता जिंदा हैं। यह बेहद चिंताजनक है, मैं सिर्फ एक सामान्य भारतीय नागरिक के तौर पर बोल रहा हूं, ये हमारी विदेश नीति का मामला नहीं है। यह पाकिस्तान का आंतरिक मामला है, लेकिन यहां एक इंसान की जिंदगी दांव पर है। थरूर ने कहा कि क्रिकेट प्रेमी और दूसरे लोग भी जानना चाहते हैं कि इमरान खान के साथ हुआ क्या है।

नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल के खिलाफ दर्ज हुई नई एफआईआर, बढ़ेंगी मुश्किलें

नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (ईओडब्ल्यू) ने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज की है। यह मामला एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) को कथित धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से हड़पने का है। एफआईआर में सोनिया और राहुल के साथ-साथ सैम पित्रोदा, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड, एजेएल और कोलकाता की कथित शेल कंपनी डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड सहित कुल आठ नाम शामिल हैं।

आरोप है कि यंग इंडियन (जिसमें गांधी परिवार की 76 प्रतिशत हिस्सेदारी है) ने मात्र 50 लाख रुपये में एजेएल को अपने

कब्जे में ले लिया, जबकि एजेएल की संपत्ति करीब 2,000 करोड़ रुपये की है। शिकायत के अनुसार, डोटेक्स ने यंग इंडियन को 1 करोड़ रुपये दिए, जिनसे कांग्रेस को 50 लाख चुकाकर एजेएल की पूरी हिस्सेदारी हासिल कर ली गई। कांग्रेस ने एफआईआर को पूरी तरह राजनीतिक प्रतिशोध बताया। पार्टी प्रवक्ता ने कहा, हमें इस एफआईआर की कोई जानकारी नहीं है। यह मोदी सरकार की एजेंसियों का दुरुपयोग है। पहले भी सभी आरोप अदालत में खारिज हो चुके हैं। जब दिल्ली पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज किए जाने पर कांग्रेस से प्रतिक्रिया मांगी गई, तो पार्टी ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि यह केस राजनीतिक बदले की कार्रवाई है और ईडी-ईओडब्ल्यू जैसी एजेंसियां सरकार के दबाव में काम कर रही हैं।

मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने बताए ड्रोन गिरने के कारण

इसरो की प्रतियोगिता के साथ ही संविधान दिवस पर की चर्चा

नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के 128वें एपिसोड के माध्यम से देशवासियों को संबोधित किया। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि नवंबर का महीना कई ऐतिहासिक और प्रेरणादायी घटनाओं का साक्षी रहा। इस दौरान उन्होंने इसरो की ड्रोन प्रतियोगित के साथ ही 26 नवंबर को मनाए गए संविधान दिवस की भी चर्चा की।

पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि संविधान दिवस के अवसर पर केंद्रीय कक्ष में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभर में भव्य आयोजनों की श्रृंखला शुरू हो चुकी है। यहां उन्होंने यह भी बताया कि 25 नवंबर को अयोध्या के राम मंदिर में धर्म ध्वजा फहराई गई, जो एक महत्वपूर्ण क्षण रहा। मन की बात में पीएम मोदी ने इसरो की ड्रोन प्रतियोगिता का उल्लेख करते हुए युवाओं के नवाचार और जिज्ञासा की सराहना की। उन्होंने कहा, कि इस प्रतियोगिता में देशभर के युवा, विशेषकर जेन-ज़ी, मंगल ग्रह जैसी परिस्थितियों में ड्रोन उड़ाने की चुनौती का सामना कर रहे थे। उन्होंने कहा, कि प्रतियोगिता के दौरान अक्सर ड्रोन उड़ते हुए अचानक गिर जाते थे, क्योंकि उनमें जीपीएस सपोर्ट बिल्कुल नहीं था। उन्होंने समझाया कि मंगल पर जीपीएस प्रणाली संभव नहीं है, इसलिए वहां ड्रोन को पूरी तरह अपने कैमरे और इन-बिल्ट सॉफ्टवेयर पर निर्भर रहकर उड़ान भरनी होती है।

पीएम मोदी ने बताया कि प्रतियोगिता में पुणे की एक टीम विजेता बनी। उनका ड्रोन भी कई बार गिरा और क्षतिग्रस्त हुआ, लेकिन टीम ने हिम्मत नहीं हारी। लगातार प्रयोग और सुधार के बाद वे मंगल जैसी परिस्थितियों में ड्रोन को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने में कामयाब हुए। पीएम मोदी ने कहा कि यह वीडियो उन्हें उस दिन की याद दिलाता है जब चंद्रयान नेटवर्क से बाहर हो गया था और पूरा देश क्षणभर के लिए निराश हो

गया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने उसी दिन से चंद्रयान-3 की सफलता की नींव रखना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि युवाओं का यही जज्बा विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

देश मे हररोज सड़क दुर्घटना में सैकड़ो की मौते और घायल होकर अपंगता का जीवन जीने को मजबूर

यातायात नियमों की अनदेखी भी हादसों का एक प्रमुख कारण है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस पाने की प्रक्रिया जितनी सरल है, उतनी ही बड़ी समस्या यह है कि बहुत से चालक नियमों को समझने, सीखने और उनका पालन करने की जिम्मेदारी नहीं निभाते। लाल बत्ती पार करना, ओवरटेकिंग करते समय सावधानी न रखना, शराब पीकर वाहन चलाना, मोबाइल पर बात करना, सीट बेल्ट न लगाना, ओवरलोडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाना,यह सब दुर्घटना को आमंत्रण देने जैसा है।

(लेखक-कांतिलाल मांडोत)

भारत जैसे विशाल और विविधताओं से भरे देश में विकास की गति निरंतर तेज़ हो रही है। शहरों से लेकर गाँवों तक सड़कों का जाल फैल रहा है, वाहन उत्पादन और उपयोग में तेजी आई है, और चलते-फिरते जीवन की इन धड़कनों ने लोगों के जीवन को नई दिशा दी है। लेकिन इसी विकास के साथ एक कड़वी सच्चाई भी उतनी ही तेजी से सामने आई है।सड़क हादसों का बढ़ता हुआ संकट। हर दिन देश में सैकड़ों लोगों की जान सड़क पर चली जाती है और हजारों लोग घायल होकर अपनी जिंदगी को दर्द, अपंगता और असहायता के बोझ तले जीने को मजबूर हो जाते हैं। यह स्थिति केवल आंकड़ों का मामला नहीं है, बल्कि हर हादसा किसी परिवार का भविष्य छीन लेता है, किसी माँ की गोद उजाड़ देता है, किसी बच्चे को अनाथ कर देता है और किसी घर से रोज़ी-रोटी कमाने वाला व्यक्ति हमेशा के लिए चला जाता है। सड़क दुर्घटनाएँ आज देश के सामने गंभीर सामाजिक, आर्थिक और मानवीय संकट बन चुकी हैं।

भारत में सड़क हादसों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। साल दर साल यह समस्या और विकराल रूप ले रही है। देश के लगभग हर राज्य में सड़क दुर्घटनाएँ सामान्य घटना बन चुकी हैं। कोई भी बड़ा शहर, कस्बा या गाँव इससे अछूता नहीं है। महानगरों की व्यस्त सड़कों पर तेज रफ्तार और अव्यवस्थित यातायात दुर्घटनाओं को जन्म देता है, जबकि ग्रामीण इलाकों में टूटी-फूटी सड़कें, गड्ढे और रोशनी की कमी मौत का कारण बन जाते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि आज भारत में सड़क दुर्घटना एक ऐसी महामारी बन चुकी है, जिसका दायरा हर दिशा में बढ़ रहा है और इसके परिणाम हर परिवार तक किसी न किसी रूप में पहुँच रहे हैं।

इन दुर्घटनाओं के सबसे बड़े कारणों में तेज रफ्तार सबसे ऊपर है। आधुनिक जीवन की जल्दबाज़ी, समय पर काम पूरा करने की हड़बड़ी और दिखावे की ललक ने तेज गति को एक फैशन की तरह स्थापित कर दिया है। खासकर युवा वर्ग मोटरसाइकिल या कार को रफ्तार की हदों तक ले जाने को रोमांच समझता है, जबकि यह रोमांच अक्सर मौत का सबब बन जाता है। दोपहिया वाहनों पर होने वाली मौतों की संख्या सबसे अधिक होती है, क्योंकि ये वाहन सड़क पर सबसे ज्यादा जोखिम उठाते हैं और चालक अक्सर सुरक्षा उपायों की अनदेखी करते हैं। हेलमेट न पहनने की आदत, गलत दिशा में वाहन चलाना और मोबाइल फोन पर बातचीत करना दोपहिया चालकों के लिए घातक सिद्ध होता है। सड़क पर एक छोटी सी चूक कई जिंदगियों को खत्म कर सकती है, परंतु बावजूद इसके लोग यातायात नियमों का पालन करने में लापरवाही बरतते हैं।

देश में सड़क हादसों का दूसरा बड़ा कारण सड़कों की खस्ताहाल स्थिति है। ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर राज्यों के प्रमुख मार्गों तक सड़कें कई जगहों पर टूटी हुई, उखड़ी हुई, संकरी और गड्ढों से भरी हुई मिलती हैं। बरसात के मौसम में ये सड़कें और ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं, क्योंकि गड्ढे पानी से भर जाते हैं और गहराई का अंदाज़ा नहीं लग पाता। रात के समय सड़क पर रोशनी की कमी दुर्घटनाओं को और बढ़ा देती है। कई बार वाहन चालक गड्ढे से बचने की कोशिश में संतुलन खो देते हैं और दुर्घटना हो जाती है। इन सड़कों से रोजाना लाखों लोग गुजरते हैं, मगर मरम्मत और रखरखाव की कमी हादसों को न्योता देती रहती है। इस स्थिति से स्पष्ट है कि सड़क विकास और सुरक्षा के बीच तालमेल का अभाव अभी भी एक बड़ी चुनौती है।

यातायात नियमों की अनदेखी भी हादसों का एक प्रमुख कारण है। भारत में ड्राइविंग लाइसेंस पाने की प्रक्रिया जितनी सरल है, उतनी ही बड़ी समस्या यह है कि बहुत से चालक नियमों को समझने, सीखने और उनका पालन करने की जिम्मेदारी नहीं निभाते। लाल बत्ती पार करना, ओवरटेकिंग करते समय सावधानी न रखना, शराब पीकर वाहन चलाना, मोबाइल पर बात करना, सीट बेल्ट न लगाना, ओवरलोडिंग, गलत दिशा में वाहन चलाना,यह सब दुर्घटना को आमंत्रण देने जैसा है। आरटीओ विभाग के नियम केवल कागज पर नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका पालन स्वयं चालक और पुलिस दोनों को कठोरता से करना चाहिए। नियमों के पालन की प्रवृत्ति समाज में मजबूती से विकसित होने पर ही दुर्घटनाओं में कमी लाना संभव है।

सड़क दुर्घटनाएँ केवल दुर्घटना नहीं होतीं, इनके साथ आर्थिक हानि भी जुड़ी होती है। कई परिवारों के लिए एक हादसा जीवन भर की बचत को खत्म कर देता है। घायल व्यक्ति के इलाज पर लाखों रुपये खर्च हो जाते हैं और कई बार जिंदगी भर के लिए नौकरी और रोज़गार का साधन भी छिन जाता है। देश की अर्थव्यवस्था को भी सड़क हादसों के कारण हर वर्ष भारी नुकसान झेलना पड़ता है। उत्पादन क्षमता घटती है, परिवारों पर बोझ बढ़ता है और समाज में असुरक्षा की भावना भी गहरी होती जाती है। जिस देश में विकास की राह पर करोड़ों लोग आगे बढ़ रहे हों, उस देश में सड़क हादसे विकास का बड़ा अवरोध बन सकते हैं।

इसके बावजूद कुछ कदम ऐसे हैं, जिन्हें अपनाकर सड़क दुर्घटनाओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है। सबसे पहली आवश्यकता है गति सीमा को समझने और उसका पालन करने की। गति सीमाएँ सुरक्षा के लिए बनती हैं, उन्हें तोड़ने के लिए नहीं। तेज गति अक्सर नियंत्रण बिगाड़ देती है और दुर्घटना की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। वाहन चालक यदि स्वयं गति पर नियंत्रण रखें तो सड़कें अधिक सुरक्षित बन सकती हैं। वाहन चलाते समय हेलमेट और सीट बेल्ट का उपयोग जीवन रक्षक उपाय की तरह अनिवार्य होना चाहिए। यह केवल नियम नहीं, बल्कि अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूकता का प्रतीक है। हेलमेट न पहनने से सिर पर चोट लगने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है और सीट बेल्ट न लगाने से आगे बैठे यात्रियों को मामूली दुर्घटना में भी गंभीर चोट लग सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हर वाहन चालक और यात्री इन सुरक्षा उपायों को हमेशा अपनाएं।

दुर्घटनाओं से बचाव के लिए शहरों और गाँवों में सड़क संरचना को मजबूत बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। नई सड़कों के निर्माण के साथ-साथ पुरानी सड़कों की नियमित मरम्मत और गड्ढों को समय पर भरवाना आवश्यक है। सड़क पर उचित संकेत बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, सड़क किनारे रोशनी, चौड़ी लेनें और पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ जैसी सुविधाएँ दुर्घटनाओं को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सरकार और स्थानीय निकायों को इस दिशा में निरंतर प्रयास करने होंगे, ताकि सड़कें सुरक्षित यात्रा के साधन बन सकें और लोग बिना किसी भय के सफर कर सकें।

इसके साथ-साथ सामाजिक जागरूकता भी बहुत जरूरी है। जब तक लोग स्वयं सड़क सुरक्षा को महत्व नहीं देंगे, तब तक केवल नियम और कानून से बदलाव संभव नहीं है। स्कूलों में बच्चों को सड़क सुरक्षा के पाठ पढ़ाए जाएँ, कॉलेजों में युवाओं को सेमिनार और कार्यशालाओं के माध्यम से यातायात नियमों के महत्व के बारे में बताया जाए, समाज के हर वर्ग को यह समझाया जाए कि सड़क सुरक्षा उसकी अपनी, परिवार की और समाज की सुरक्षा से सीधे जुड़ी हुई है। मीडिया, सोशल मीडिया, एनजीओ और सरकारी संस्थानों को मिलकर एक व्यापक अभियान चलाना चाहिए, ताकि लोग सड़क पर जिम्मेदारी से व्यवहार करना सीखें।

इन सबके बीच यह भी समझना जरूरी है कि सड़क सुरक्षा केवल चालक की ही जिम्मेदारी नहीं है। पैदल यात्रियों को भी सड़क पार करते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कई हादसे इसलिए भी होते हैं क्योंकि लोग बिना देखे सड़क पार करने की कोशिश करते हैं। मोबाइल फोन पर व्यस्त रहना, हेडफोन लगाकर सड़क पर चलना या अचानक सड़क पर उतरना दुर्घटना को जन्म देता है। पैदल यात्री और वाहन चालक दोनों को एक-दूसरे की सुरक्षा का सम्मान करते हुए यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।

सड़क हादसों की बढ़ती समस्या हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर कब तक हम अपनी लापरवाही के कारण जान से हाथ धोते रहेंगे। यह केवल सरकार का विषय नहीं है और न ही केवल पुलिस की जिम्मेदारी। यह पूरा समाज का विषय है, प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। सड़कें तभी सुरक्षित होंगी जब लोग स्वयं नियमों का पालन करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। एक स्वस्थ और सुरक्षित समाज की नींव जागरूकता, अनुशासन और जिम्मेदारी पर ही टिकी होती है। सड़क सुरक्षा का पालन केवल जीवन बचाने का कार्य नहीं है, यह मानवता के प्रति हमारा कर्तव्य भी है।

आज जरूरत इस बात की है कि हम सड़क सुरक्षा को एक गंभीर विषय के रूप में समझें। सड़क पर उतरते समय सुरक्षा के हर नियम को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। तेज गति से निजात पाएँ, मोबाइल फोन से दूरी बनाए रखें, हेलमेट और सीट बेल्ट हमेशा पहनें, शराब पीकर वाहन न चलाएं, वाहन की नियमित जांच करवाते रहें और सड़क संरचना को मजबूत बनाने की दिशा में सरकार के प्रयासों का समर्थन करें। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति इन बातों का पालन करे, तो सड़क दुर्घटनाओं की संख्या निश्चित रूप से कम होगी और देश का विकास अधिक सुरक्षित और मजबूत आधार पर खड़ा होगा।

सड़कें जीवन को आगे बढ़ाने का माध्यम हैं, न कि जीवन समाप्त करने का रास्ता। यह बात समझना और दूसरों को समझाना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। यदि हम आज जागरूक होंगे, तो भविष्य की पीढ़ियाँ एक सुरक्षित भारत देखेंगी।एक ऐसा भारत जहाँ सड़कें प्रगति की राह बनेंगी, न कि आँसुओं की बूँदों का कारण।

संपादकीय

नक्सली हिंसा से मुक्ति

इसमें दो राय नहीं है कि शीर्ष माओवादी कमांडर हिडमा का मुठभेड़ में मारा जाना वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ देश की दशकों पुरानी लड़ाई में निर्णायक सफलताओं में से एक है। संगठन के शीर्ष नेतृत्व पर प्रहार से देश नक्सली हिंसा से मुक्ति की राह में कामयाबी की तरफ बढ़ा है। लगभग तीन दशकों तक हिडमा बस्तर में चौंकाने वाली रणनीतियों से बड़े हमलों को अंजाम देता रहा है। बताते हैं कि वह सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हुए सबसे घातक हमलों का मास्टरमाइंड रहा है। छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश की सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा हिडमा व उसकी पत्नी समेत छह नक्सलियों को मार गिराना केंद्र सरकार की उस रणनीति की सफलता को दर्शाता है, जिसमें 31 मार्च 2026 तक देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का लक्ष्य तय किया गया था। इसी साल मार्च में बीजापुर में जब 50 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया था तब गृहमंत्री अमित शाह ने उनके फैसले का स्वागत करते हुए सभी का पुनर्वास करके, उन्हें राष्ट्र की मुख्यधारा से जोड़ने की बात कही थी। निस्संदेह, हिडमा का सफाया नक्सलवादी संचालन ढांचे के खात्मे और भारत में उग्रवाद विरोधी तंत्र की एक महत्वपूर्ण जीत का संकेत है। गुरिल्ला आर्मी की बटालियन-1 के कमांडर के रूप में हिडमा का उदय-वंचित युवाओं की भर्ती करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और हथियार बनाने की उग्रवादी क्षमता का प्रतीक रहा है। उसकी गिनती सबसे खूंखार नक्सलवादी कमांडर के रूप में होती रही है। अब वर्ष 2010 का दंतेवाड़ा हमला हो या 2013 का झीरम घाटी हमला, पिछले बीस वर्षों में हुए लगभग सभी बड़े नक्सली हमलों के पीछे हिडमा की रणनीति बतायी जाती है। वहीं दूसरी ओर इन हमलों ने भारत की सुरक्षा रणनीति को नया रूप दिया। इससे पहले इसी साल मई में सुरक्षाबलों ने माओवादी संगठन के जनरल सक्रेटरी बसवराजू को भी मार गिराया था। वहीं इस साल विभिन्न मुठभेड़ों में तीन सौ से अधिक नक्सली मारे जाने से नक्सलवाद छोटे इलाके में सिमटा है। निस्संदेह, सुरक्षा बलों की तत्परता और सुनियोजित अभियानों से नक्सलवाद कमजोर जरूर हुआ है, लेकिन जरूरत उन परिस्थितियों को दूर करने की है, जिन्होंने नक्सलवाद को जन्म दिया। आवश्यकता उन मुद्दों के समाधान की है, जिसके चलते माओवाद को जड़ें जमाने का मौका मिला। बस्तर का अधिकांश क्षेत्र लगातार विकास की विसंगतियों, खनन से संसाधनों के मनमाने दोहन, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण विस्थापन व जनजातीय समुदायों और राज्य के बीच विश्वास की कमी से जूझता रहा है। अभी भी आदिवासियों की बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं, गुणवत्तापूर्ण स्कूलों, भूमि अभिलेखों और कल्याणकारी योजनाओं तक पूरी तरह पहुंच नहीं बन पायी है। दूर-दराज के कई गांवों में ग्रामीणों को प्रशासन का अनुभव नागरिक संस्थानों के बजाय सुरक्षा बलों की मौजूदगी से ही होता है। दरअसल, विकास की नीतियों से जुड़े वायदों और हकीकत का अंतर ही आदिवासियों में असंतोष को बढ़ाता है। भले ही माओवाद का प्रभाव कम हो जाए। वास्तव में जब तक शासन जिम्मेदार, जवाबदेह और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील नहीं बन पाता, तब तक माओवादी संस्कृति के पनपने की आशंकाएं बनी रहेंगी। दरअसल,क्षेत्र में तंत्र की अनुपस्थिति ने ही चरमपंथियों को आदिवासियों के रक्षक के रूप में पेश करने का मौका दिया। निस्संदेह, सुरक्षा बलों ने माओवाद के खात्मे की दिशा में बड़ा काम कर दिया है, अब राज्यों के पास इस रणनीतिक जीत को स्थायी शांति में बदलने का अच्छा अवसर है।

रक्त - रिबन, जीव- रिबन : एड्स के अंधेरे में आशा की लाल किरण

(लेखक - दिलीप कुमार पाठक)

विश्व एड्स दिवस 1 दिसम्बर)

एड्स एक ख़तरनाक बीमारी है, मूलत: असुरक्षित यौन संबंध बनाने से एड्स के जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाते हैं यूएनएड्स के मुताबिक़, अब तक 34 मिलियन लोग एड्स से ग्रसित हैं और 2010 तक 2.7 मिलियन लोग इस इंफेक्शन के संपर्क में आए हैं, जिसमें से 3 लाख 90 हजार बच्चे भी इसकी चपेट में आएं, वहीँ 1.8 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है।

एड्स के बारे में विस्तारपूर्वक जानने से पहले एड्स सम्बन्धित रेड रिबन के बारे में भी जानना ज़रूरी हो जाता है द्य एचआईवी से ग्रस्त लोगों के प्रति जागरूकता और समर्थन का एक सार्वभौमिक प्रतीक है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, जब बारह कलाकार न्यूयॉर्क के एचआईवी-जागरूकता कला संगठन, विज़ुअल एड्स के लिए एक नई परियोजना पर चर्चा करने के लिए मिले थे। यहीं पर उन्हें वह रंग मिला जो उस दशक के सबसे प्रसिद्ध प्रतीकों में से एक बन गया द्य लाल रिबन, जिसे एचआईवी से ग्रस्त लोगों के प्रति जागरूकता और समर्थन का प्रतीक माना जाता था। कलाकार एचआईवी से ग्रस्त लोगों के प्रति करुणा की एक दृश्य अभिव्यक्ति बनाना चाहते थे और उन्होंने लाल रंग को उसकी निर्भीकता और जुनून, हृदय और प्रेम के साथ उसके प्रतीकात्मक जुड़ाव के लिए चुना।

विश्व एड्स दिवस की शुरूआत 1 दिसंबर 1988 को हुई थी जिसका उद्देश्य, एचआईवी एड्स से ग्रसित लोगों की मदद करने के लिए धन जुटाना, लोगों में एड्स को रोकने के लिए जागरूकता फैलाना और एड्स से जुड़े मिथ को दूर करते हुए लोगों को शिक्षित करना था। दरअसल, विश व एड्स दिवस आपको याद कराता है कि ये बीमारी अभी भी हमारे-आपके बीच है और इसे लगातार खत्म की कोशिशों में आपको भी आगे आना होगा। इस बीमारी का काफ़ी देर बाद पता चलता है और मरीज भी एचआईवी टेस्ट के प्रति सजग नहीं रहते, इसलिए अन्य बीमारी का भ्रम बना रहता है द्य आमतौर पर देखा गया है कि एड्स अधिकतर उन देशों में है जहां लोगों की आय बहुत कम है, या जो लोग मध्यवर्गीय परिवारों से ताल्लुक रखते हैं। बहरहाल, एचआईवी एड्स आज दुनिया भर के सभी महाद्वीपों में महामारी की तरह फैला हुआ है जो कि पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन के लिए एक बड़ा खतरा है और जिसे मिटाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

भारत में आज भी जिन्हें एड्स है, वे यह बात स्वीकारने से कतराते हैं। इसकी वजह है घर में, समाज में होने वाला भेदभाव। कहीं न कहीं आज भी एचआईवी पॉजीटिव व्यक्तियों के प्रति भेदभाव की भावना रखी जाती है। यदि उनके प्रति समानता का व्यवहार किया जाए तो स्थिति और भी सुधर सकती है। बात अगर जागरूकता की करें तो लोग जागरूक ज़रूर हुए हैं इसलिए आज इसके प्रति काउंसलिंग करवाने वालों की संख्या बढ़ी है। पर यह संख्या शहरी क्षेत्र के और मध्यम व उच्च आय वर्ग के लोगों तक ही सीमित है। निम्न वर्ग के लोगों में अभी भी जानकारी का अभाव है। इसलिए भी इस वर्ग में एचआईवी पॉजीटिव लोगों की संख्या अधिक है। जबकि बहुत सी संस्थाएँ निम्न आय वर्ग के लोगों में इस बात के प्रति जागरूकता अभियान चला रही हैं। लोग कारण को जानने के बाद भी सावधानियाँ नहीं बरतते। जिन कारणों से एड्स होता है उससे बचने के बजाए अनदेखा कर जाते हैं। इसमें अधिकांश लोग असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित रक्त के कारण एड्स की चपेट में आते हैं।

एड्स के ख़िलाफ़ आज शहरों में अनेक समाज सेवी और सरकारी संस्थाएँ कार्य कर रही हैं। इनका उद्देश्य लोगों को जागरूक करना, एड्स के साथ जी रहे लोगों को समाज में उचित स्थान दिलाना, उनका उपचार कराना आदि है। इन संस्थाओं में से

कुछ हैं फेमेली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, विश्वास, भारतीय ग्रामीण महिला संघ, मध्यप्रदेश वॉलेन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन, ज़िला स्तरीय नेटवर्क, वर्ल्ड विजन आदि। फेमेली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंदौर शाखा सेक्सुअलिटी एजुकेशन, काउंसलिंग, रिसर्च, ट्रेनिंग/थैरेपी (एसईसीआरटी) परियोजना के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रही है। संस्था किशोर बालक-बालिकाओं एवं युवाओं को किशोरावस्था, एड्स आदि के बारे में जानकारी देकर जागरूक बनाने का कार्य कर रही है। जागरूकता अभियान के तहत स्कूल-कॉलेज तो चुने ही जाते हैं पर जो लोग स्कूल-कॉलेज नहीं जाते उनके लिए कम्युनिटी प्रोग्राम या नुक्कड़ नाटक कर समझाया जाता है। एड्स की रोकथाम के लिए किए जा रहे प्रयास तब ही सफल होंगे जब सरकार, जनता और समाजसेवी संस्थाएँ मिलकर प्रयास करें।

(लेखक पत्रकार हैं)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

विनम्रता का पाठ

चिंतन मनन

पंडित विद्याभूषण बहुत बड़े विद्वान थे। दूर-दूर तक उनकी चर्चा होती थी। उनके पड़ोस में एक अशिक्षित व्यक्ति रहते थे-रामसेवक। वे अत्यंत सज्जन थे और लोगों की खूब मदद किया करते थे। पंडित जी रामसेवक को ज्यादा महत्व नहीं देते थे और उनसे दूर ही रहते थे। एक दिन पंडित जी अपने घर के बाहर टहल रहे थे। तभी एक राहगीर उधर आया और मोहल्ले के एक दुकानदार से पूछने लगा-भाई यह बताओ कि पंडित विद्याभूषण जी का मकान कौन सा है। यह सुनकर पंडित जी की उत्सुकता बढ़ी। वह सोचने लगे कि आखिर यह कौन है जो उनके घर का पता पूछ रहा है। तभी दुकानदार ने उस राहगीर से कहा-मुझे तो किसी पंडित जी के बारे में नहीं मालूम। तब राहगीर ने कहा-क्या रामसेवक जी का घर जानते हो?

दुकानदार ने हंसकर कहा-अरे भाई उन्हें कौन नहीं जानता। वे बड़े भले आदमी हैं। फिर उसने हाथ दिखाकर कहा- वो रहा रामसेवक जी का घर। फिर दुकानदार ने राहगीर से सवाल किया-लेकिन आपको काम किससे है? पंडित जी से या रामसेवक जी से? राहगीर कहने लगा-भाई काम तो मुझे रामसेवक जी से है। पर उन्होंने ही बताया था कि उनका मकान पंडित विद्याभूषण जी के पास है। यह सुनकर पंडित जी ग्लानि से भर उठे। सोचने लगे कि उन्होंने हमेशा ही रामसेवक को अपने से हीन समझा और उसकी उपेक्षा की पर रामसेवक कितना विनम्र है। वह खुद बहुत प्रसिद्ध होते हुए भी उन्हें ज्यादा महत्व देता है। उसी रात पंडित जी रामसेवक के घर गए और उससे क्षमायाचना की। फिर दोनों गहरे मित्र बन गए।

विचार मंथन

पल्लवी पटेल के चुनाव आयोग के खिलाफ बगावती तेवर

(लेखक- सनत जैन)

भारत में पैदा हुई पल्लवी पटेल ने कहा है, वह भारत में जन्मी हैं। भारतीय नागरिक हैं, सभी दस्तावेज उनके पास मौजूद हैं। मत देना उनका संवैधानिक अधिकार है। वह एसआईआर का फॉर्म नहीं भरेंगी। देखते हैं उन्हें मत देने से कौन रोकता है। भारत का लोकतंत्र दुनिया के सबसे विशाल और जटिल लोकतांत्रिक ढांचों में एक है। यहां हर नागरिक को वोट देने का संवैधानिक अधिकार मिला है। ऐसे में हाल के दिनों में एसआईआर फॉर्म को लेकर जो विवाद देखने को मिल रहा है वह केवल प्रशासनिक प्रक्रिया का मामला नहीं, वरन लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण से भी जुडा हुआ है। जब कोई नागरिक यह कहता है, मैं भारत में पैदा हुई हूं, मेरे पास सभी दस्तावेज हैं, मत देना मेरा संवैधानिक अधिकार है। तो यह बयान केवल व्यक्तिगत नाराज़गी का नहीं, बल्कि उस व्यापक चिंता का है, एसआईआर के बहाने मतदाताओं को उनके संवैधानिक अधिकार से बेदखल किया जा रहा है। जो वर्तमान में सघन मतदाता परीक्षण के नाम पर देशभर में दिखाई दे रहा है। मतदाता सूची का अपडेट होना जरूरी है। इसमें दो मत नहीं है, लेकिन जब भारत में जन्मे भारतीय नागरिकों से ही दस्तावेज या अन्य किसी प्रक्रिया के नाम पर मतदाताओं के वोट काटे जाएं, आम नागरिकों के मन में भय पैदा किया जाए, मतदाताओं को यह डर और भय हो जाए, उनका नाम कहीं वोटर लिस्ट से ना कट जाए। तो ऐसी स्थिति में यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक नहीं, वरन दमनकारी प्रतीत हो रही है। एसआईआर को लेकर यही समस्या सामने आ रही है। लगातार शिकायतें आ रही हैं। बीएलओ पर असाधारण दबाव डाला जा रहा है। फॉर्म भरवाने में अनावश्यक जल्दबाजी की जा रही है। मतदाताओं को समझाए बिना उनसे दस्तावेज मांगे जा रहे हैं। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? भारत का कानून स्पष्ट रूप से कहता है, जो नागरिक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, जिसके पास वैध पहचान प्रमाण है, उसे मतदाता के रूप में पंजीकृत करना चुनाव आयोग की संवैधानिक जिम्मेदारी है। यह अधिकार किसी अतिरिक्त फॉर्म, किसी नई प्रक्रिया या किसी सरकारी निर्णय के आधार पर नहीं छीना जा सकता है। नागरिकता प्रमाणित करने के लिए हमारे पास पहले से ही आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट, राशन कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र जैसे अनेक दस्तावेज मौजूद हैं। जो हमारे जन्म और भारतीय नागरिक होने का सबूत हैं। इसके बाद भी चुनाव आयोग द्वारा एक नई प्रक्रिया लागू की जाती है तो उसका उद्देश्य पारदर्शी होना चाहिए। नागरिकों को यह भरोसा दिलाया जाना चाहिए, मतदाता सूची के सघन परीक्षण में इसका उपयोग किसी के राजनीतिक लाभ या सामाजिक भेदभाव के लिए नहीं किया जाएगा। यह विश्वास दिलाने में चुनाव आयोग पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। सबसे बड़ी चिंता यह है, एसआईआर के नाम पर कमजोर वर्गों— दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और दूर-दराज के ग्रामीण मतदाताओं के नाम बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से काटे जाने की आशंका शुरू से ही देखने को मिल रही है। बिहार की एसआईआर के समय यही आशंका व्यक्त की गई थी, जो सही साबित हुई। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मामला सुनवाई में लंबित है। इसी बीच बिहार विधानसभा के चुनाव हो गए। लाखों मतदाताओं के नाम काट दिए गए। जिनके नाम जोड़े गए उनकी सूची नहीं दी गई। चुनाव आयोग जिस तरह की गोपनीयता और अपारदर्शिता के साथ काम कर रहा है, उसके कारण अब मतदाताओं को चुनाव आयोग के ऊपर विश्वास भी नहीं रह गया है। लोकतंत्र तभी मजबूत होता है जब हर नागरिक को मतदान के समान अधिकार मिलें। उसके मत का सम्मान हो, उसे किसी भी प्रकार की शंका, दबाव या भय में मतदान ना करना पड़े। वह अपने अधिकार किसी योग्य प्रतिनिधि को ही मत के माध्यम से दे सके। लोकतांत्रिक व्यवस्था में मत देना सिर्फ एक अधिकार नहीं, बल्कि नागरिक होने का सबसे महत्वपूर्ण प्रमाण है। एसआईआर पर उठ रहे सवालों को अनसुना नहीं किया जा सकता। सरकार, चुनाव आयोग और उच्चतम न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए। कोई भी ऐसी प्रक्रिया ना अपनाई जाए, जिससे नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया जाये। दस्तावेजों की आड़ में उन्हें कोर्ट-कचहरी में परेशान किया जाए। उनकी नागरिकता और उनके मौलिक अधिकारों को एसआईआर के माध्यम से खत्म करने की किसी भी चेष्टा को भारत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। नागरिक स्वतंत्रता से बड़ा कोई अधिकार नहीं हो सकता है। यह गरीब से गरीब आदमी को बिना किसी भेदभाव के भारत के संविधान ने दिया है। महिला, पुरुषों को समान अधिकार हैं।

ऐसी स्थिति में जिन लोगों ने भारत में जन्म लिया है, दस्तावेजों के नाम पर यदि उनके वोट देने के अधिकार को खत्म किया जाता है। इसका विरोध एवं बगावती तेवर अब पल्लवी पटेल जैसे लोग सामने आकर करने लगे हैं। यह चिंता का विषय है।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

रेपो दर में कटौती कर सकता है रिजर्व बैंक

मुंबई भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की इस सप्ताह होने वाली बैठक में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। रेपो दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण देता है। एमपीसी की बैठक 03 से 05 दिसंबर को होने वाली है। इससे पहले अक्टूबर को हुई बैठक में रेपो तथा अन्य नीतिगत दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पिछली बार आरबीआई गर्वनर ने कहा था कि मुद्रास्फीति की कम दरों को देखते हुए रेपो दरों में कटौती की गुंजाइश है, लेकिन केंद्रीय बैंक और आंकड़ों का इंतजार करेगा। वह वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में की गयी कटौती तथा अमेरिका में भारतीय वस्तुओं पर उच्च आयात के प्रभाव को देखना चाहेगा।

चीन की कारखाना गतिविधियों में नवंबर में लगातार आठवें महीने गिरावट

हांगकांग चीन की कारखाना गतिविधियों में नवंबर में लगातार आठवें महीने गिरावट आई है। एक आधिकारिक सर्वे में यह जानकारी दी गई है। हालांकि, अमेरिका-चीन के बीच व्यापार के मोर्चे पर समझौता हो गया है, लेकिन इसके बावजूद चीन की चुनौतियां बनी हुई हैं। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने कहा कि आधिकारिक विनिर्माण खरीद प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) नवंबर में थोड़ा बढ़कर 49.2 हो गया, जो अक्टूबर में 49 था। पीएमआई के 50 से नीचे होने का आशय गतिविधियों में संकुचन से है। पीएमआई गतिविधियों में यह गिरावट विश्लेषकों के अनुमान के मुताबिक है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी शुल्क में कटौती के बाद अमेरिकी बाजार में चीन का निर्यात प्रतिस्पर्धा हासिल कर सकता है। लेकिन यह कहना जल्दबाजी होगी कि व्यापार समझौते के बाद निर्यात ने फिर से रफ्तार पकड़ी है या नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिका 30 अक्टूबर से चीनी उत्पादों पर शुल्क में कटौती करेगा। इससे चीन के निर्यात और विनिर्माण को लेकर कुछ उम्मीद बंधी है।

एसबीआई को कॉरपोरेट ऋण में दो अंकीय वृद्धि की उम्मीदः चेयरमैन सीएस शेट्टी

आर्थिक सुधार और मजबूत पाइपलाइन से बचे हुए दो तिमाहियों में ऋण में तेजी की संभावना

नई दिल्ली भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को उम्मीद है कि चालू वित्त वर्ष की बचे हुए दो तिमाहियों में कॉरपोरेट ऋण में दो अंकीय वृद्धि देखने को मिलेगी। बैंक के चेयरमैन सीएस शेट्टी ने हाल ही में एक साक्षात्कार में कहा कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार और बैंक की मजबूत ऋण पाइपलाइन के कारण कॉरपोरेट ऋण में तेजी आएगी। शेट्टी ने बताया कि एसबीआई के पास लगभग 7 लाख करोड़ रुपए के मंजूर ऋण हैं, जिनमें बिना इस्तेमाल की गई कार्यशील पूंजी सीमा और मियादी ऋण शामिल हैं। ये ऋण वर्तमान में वितरण प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा कई परियोजना ऋण पर अभी बातचीत चल रही है, जो भविष्य में बैंक की ऋण वृद्धि को और मजबूत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से कॉरपोरेट ऋण पिछड़ रहा था, लेकिन दूसरी तिमाही में इसमें 7.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। शेष दो तिमाहियों में बैंक नीचे दो अंकों की वृद्धि की उम्मीद कर रहा है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार के साथ कार्यशील पूंजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जो हर तिमाही के साथ और मजबूत हो रहा है। एसबीआई चेयरमैन ने यह भी स्पष्ट किया कि बैंक को ऋण वृद्धि बढ़ाने और अगले पांच-छह साल में 15 प्रतिशत का पूंजी पर्याप्तता अनुपात बनाए रखने के लिए अतिरिक्त इक्विटी पूंजी की आवश्यकता शायद नहीं पड़ेगी।

आरबीआई पॉलिसी से पहले बैंकों ने सस्ते किए होम लोन

कई बैंकों ने ब्याज दरें घटाकर 7 फीसदी से शुरू कीं

नई दिल्ली

आरबीआई की अगली मौद्रिक नीति की घोषणा से ठीक पहले देशभर के बैंकों ने होम लोन की ब्याज दरों में कमी कर दी है। इसका सीधा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा जो नया घर खरीदने या निर्माण करने के लिए किफायती फाइनेंस की तलाश में थे। मौजूदा हालात में कई बैंक न्यूनतम 7 प्रतिशत तक की सालाना ब्याज दर पर लोन उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे मासिक किस्तों में उल्लेखनीय कमी आएगी। पब्लिक सेक्टर बैंकों में बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने नवंबर 2025 तक के लिए 7.35 प्रतिशत की शुरुआती दरों की घोषणा की है। केनरा बैंक 7.40 प्रतिशत और देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई 7.50 प्रतिशत सालाना से ब्याज दरें ऑफर कर रहा है। एसबीआई का रेपो-लिंक्ड बेंचमार्क रेट 1 अगस्त 2025 से लागू है, जिसके आधार पर ग्राहकों की क्रेडिट प्रोफाइल के मुताबिक ब्याज तय किया जाता है। दूसरी ओर, प्राइवेट सेक्टर में एचडीएफसी बैंक 7.90 प्रतिशत,

एक्सिस बैंक 8.35 प्रतिशत और आईसीआईसीआई बैंक 8.75 प्रतिशत से होम लोन दे रहे हैं। ये सभी बैंक 30 साल तक की लंबी अवधि के साथ अधिकतम 90 प्रतिशत तक फाइनेंस उपलब्ध करा रहे हैं।

डालमिया सीमेंट को 266.3 करोड़ के कर नोटिस

नई दिल्ली डालमिया सीमेंट (भारत) लिमिटेड (डीसीबीएल), जो डालमिया भारत की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है, को बिक्री कर कार्यालय से कुल 266.3 करोड़ रुपये के नोटिस प्राप्त हुए हैं। कंपनी ने शेयर बाजारों को सूचित किया कि ये नोटिस सेंट्रल जीएसटी/तमिलनाडु जीएसटी कानून 2017 की धारा 74 के तहत आकलन वर्ष 2019-20 और 2022-23 के लिए लालगुडी, तिरुचिरापल्ली, तमिलनाडु के अधिकारी द्वारा जारी किए गए हैं। आकलन वर्ष 2019-20 के लिए, अधिकारियों ने 128.39 करोड़ रुपये का कर और 19.25 करोड़ रुपये का जुर्माना मांगा है, जबकि 2022-23 के लिए 59.32 करोड़ रुपये का कर और समान राशि का जुर्माना निर्धारित किया गया है। कंपनी ने बताया कि यह नोटिस कर योग्य कारोबार और इनपुट टैक्स क्रेडिट में अंतर से संबंधित हैं। कंपनी ने कहा कि उसे ये आदेश 28 नवंबर, 2025 को मिले हैं।

दो माह में दो दर्जन कंपनियां आईपीओ लाने की तैयारी में, 40,000 करोड़ जुटाएंगी

पिछले साल 91 आईपीओ के जरिए कुल 1.6 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए थे

नई दिल्ली भारतीय शेयर बाजार में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) का आकर्षण इस साल तेजी से बढ़ रहा है। मर्चेंट बैंकरों के अनुसार, अगले दो महीनों के दौरान आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी, मीसो और जे नियर ग्रीन इनर्जीसमेत लगभग 24 कंपनियां अपने आईपीओ लाने की तैयारी में हैं। इन आईपीओ के जरिए लगभग 40,000 करोड़ रुपये जुटाने की संभावना है। इस समय की मजबूत पाइपलाइन में कृत्रिम मेधा (एआई) कंपनी फ्रेक्टल एनालिटिक्स, होम और स्लीप समाधान ब्रांड वाके फिट, टेक्नोलॉजी आधारित सुरक्षा और निगरानी कंपनी इनोवे टिव व्यू इं डिया और हॉस्पिटल श्रृंखला पार्क मे डि वर्ल्ड जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। यह संकेत देता है कि कंपनियों का भरोसा मजबूत है और निवेशक न केवल सूचीबद्धता के दिन लाभ के लिए बल्कि लंबी अवधि के निवेश के लिए भी उत्सुक हैं। विशेष रूप से, बड़ी, मझोली और छोटी सभी आकार की कंपनियां आईपीओ ला रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तेजी का श्रेय बढ़ती खुदरा भागीदारी और घरेलू निवेश प्रवाह को जाता है। इस साल अब तक 96 कंपनियां शेयर बाजार में सूचीबद्ध हुई हैं और उन्होंने आईपीओ के माध्यम से कुल 1.6 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं। इनमें से 40 से अधिक कंपनियां केवल पिछले तीन महीनों में सूचीबद्ध हुई हैं, जो प्राथमिक बाजार में बढ़ती गतिविधियों को दर्शाता है। पिछले साल, 2024 में 91 आईपीओ के जरिए कुल 1.6 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए थे।

सेंसेक्स की शीर्ष 10 कंपनियों में से सात का मार्केट कैप 96,201 करोड़ बढ़ा

सबसे अधिक लाभ में रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज फाइनेंस, सबसे अधिक गिरावट भारती एयरटेल में रही

नई दिल्ली

बीते सप्ताह सेंसेक्स की शीर्ष 10 कंपनियों में से सात के बाजार पूंजीकरण (मार्केट कैप) में सामूहिक रूप से 96,200.95 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई। सबसे ज्यादा फायदा रिलायंस इंडस्ट्रीज और बजाज फाइनेंस को हुआ। रिलायंस इंडस्ट्रीज का बाजार पूंजीकरण 28,282.86 करोड़ रुपये बढ़कर 21,20,335.47 करोड़ रुपये हो गया। बजाज फाइनेंस का मूल्यांकन 20,347.52 करोड़ रुपये बढ़कर 6,45,676.11 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक का बाजार पूंजीकरण 13,611.11 करोड़ रुपये बढ़कर 15,48,743.67 करोड़ रुपये हुआ, जबकि आईसीआईसीआई बैंक 13,599.62 करोड़ रुपये बढ़कर 9,92,725.97 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। हिंदुस्तान यूनिलीवर का बाजार मूल्यांकन 7,671.41 करोड़ रुपये बढ़कर 5,79,644.16 करोड़ रुपये हुआ। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का बाजार पूंजीकरण 6,415.28 करोड़ रुपये बढ़कर 9,04,185.15 करोड़ रुपये और इन्फोसिस का मूल्यांकन 6,273.15 करोड़ रुपये बढ़कर 6,47,961.98 करोड़ रुपये रहा। इस रुख के उलट भारती एयरटेल का बाजार पूंजीकरण 35,239.01 करोड़ रुपये घटकर 11,98,040.84

करोड़ रुपये रह गया। एलआईसी का मूल्यांकन 4,996.75 करोड़ रुपये घटकर 5,65,581.29 करोड़ रुपये और टीसीएस का पूंजीकरण 3,762.81 करोड़ रुपये घटकर 11,35,952.85 करोड़ रुपये पर आ गया। शीर्ष 10 कंपनियों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले स्थान पर कायम रही। इसके बाद क्रमशः एचडीएफसी बैंक, भारती एयरटेल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इन्फोसिस, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एलआईसी का स्थान रहा।

भारत 2050 तक 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने की राह पर

8.2 फीसदी रियल जीडीपी ग्रोथ ने बढ़ाई उम्मीदें, नॉमिनल ग्रोथ 12 फीसदी तक पहुंची

नई दिल्ली

भारत ने 2050 तक 30 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनने का बड़ा लक्ष्य तय किया है, और ताज़ा आर्थिक संकेतक बताते हैं कि यह लक्ष्य अब पहले से अधिक संभव नजर आ रहा है। दूसरी` तिमाही के` वित्त वर्ष 26 में देश की रियल जीडीपी ग्रोथ 8.2 फीसदी दर्ज की गई, जो बताती है कि अर्थव्यवस्था मजबूत रफ्तार से आगे बढ़ रही है। भारत की मौजूदा नॉमिनल जीडीपी लगभग 4.15 ट्रिलियन डॉलर है और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पूरे 25 साल का समय उपलब्ध है। आर्थिक गणनाओं के अनुसार, यदि भारत लगातार 8.23 फीसदी नॉमिनल ग्रोथ रेट बनाए रखता है, तो 2050 तक 30 ट्रिलियन डॉलर का स्तर हासिल किया जा सकता है। मौजूदा परिदृश्य में 8.2 फीसदी रियल ग्रोथ के साथ इन्फ्लेशन जोड़ने पर नॉमिनल ग्रोथ 12 फीसदी से अधिक रहती है, यानी भारत लक्ष्य के लिए आवश्यक ग्रोथ से भी तेज़ चल रहा है। विश्लेषण बताते हैं कि अगर भारत अगले 25

वर्षों तक 8.2 फीसदी रियल ग्रोथ बनाए रखता है, तो 2050 में जीडीपी लगभग 30 ट्रिलियन डॉलर के पास पहुंच सकती है। वहीं यदि नॉमिनल ग्रोथ 12 फीसदी पर बनी रहती है, तो भारत 70 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था भी बन सकता है।

एपिस इंडिया का बड़ा बोनस इश्यू, निवेशकों के लिए खास मौका

24:1 रेशियो में बोनस शेयर, रिकॉर्ड डेट 5 दिसंबर

मुंबई एपिस इंडिया लिमिटेड (सिक्योरिटी कोडः 506166), जो हनी, फूड प्रोडक्ट्स और एफएमसीजी सेक्टर में काम करती है, इस हफ्ते अपने शेयरधारकों के लिए बड़ा अवसर लेकर आ रही है। कंपनी ने 24:1 के बेहद बड़े अनुपात में बोनस शेयर जारी करने की घोषणा की है। इसका मतलब है कि निवेशकों के पास जितने भी शेयर हैं, उन्हें हर 1 शेयर पर 24 नए बोनस शेयर मिलेंगे। कंपनी ने 5 दिसंबर को एक्स-डेट और रिकॉर्ड डेट घोषित की है। इस तारीख तक जिन निवेशकों के पास शेयर होंगे, वे इस बोनस का लाभ उठा सकेंगे। बोनस इश्यू का मुख्य उद्देश्य कंपनी के मजबूत रिजर्व और वित्तीय स्थिति का संकेत देना होता है। यह निवेशकों के लिए फ्री शेयर पाने का मौका है और इसे अक्सर सकारात्मक संकेत माना जाता है। बोनस शेयर मिलने के बाद निवेशकों की होल्डिंग बढ़ जाती है, हालांकि शेयर की कीमत अपने अनुपात में एडजस्ट हो जाती है। इससे कुल वैल्यू लगभग वही रहती है, लेकिन शेयर की संख्या बढ़ने से लिक्विडिटी तेज होती है और नए निवेशकों के लिए प्रवेश आसान हो जाता है।

तेल-तिलहन बाजार में सुधार के बावजूद सोयाबीन तिलहन दाम में गिरावट

सरसों, मूंगफली तेल-तिलहन, सोयाबीन तेल, पामतेल/पामोलीन और बिनौला तेल के दाम बढ़े

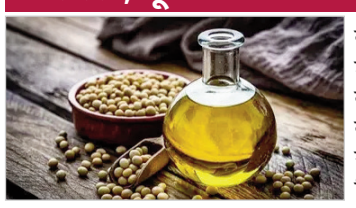

स्थानीय मांग में सुधार होने के बावजूद मूंगफली की खपत सीमित

नई दिल्ली

बीते सप्ताह देश के तेल-तिलहन बाजार में मिश्रित रुझान दिखा। सरसों, मूंगफली तेल-तिलहन, सोयाबीन तेल, पामतेल और पामोलीन तथा बिनौला तेल के दाम में सुधार हुआ, जबकि सोयाबीन तिलहन के दाम गिरावट के साथ बंद हुए। सोयाबीन डी-आयल्ड केक की कमजोर स्थानीय मांग के कारण मिल वालों की खरीदारी प्रभावित रही, जिससे सोयाबीन तिलहन पर दबाव बना। सरसों के भाव में सुधार हुआ है। दाना 7,110-7,160 रुपये प्रे ति क्विंटल, दादरी तेल 14,725 रुपये प्रे ति क्विंटल और पक्की व कच्ची घानी तेल क्रमशः 2,470-2,570 और 2,470-2,605 रुपये प्रे ति टिन पर बंद हुए। सरसों के दाम एमएसपी से ऊपर चल रहे हैं, लेकिन आगामी दो-तीन महीनों में नई फसल आने की संभावना और आयातित तेलों से दबाव का असर हो सकता है। सोयाबीन की स्थिति कमजोर बनी हुई है। दाना 4,550-4,600 रुपये और लूज 4,250-4,300 रुपये प्रे ति क्विंटल पर बंद हुए, जो एमएसपी से काफी नीचे हैं। सोयाबीन तेल में दिल्ली 13,450 रुपये और इंदौर 13,100 रुपये प्रे ति क्विंटल पर सुधार दिखा। आयातक पहले लागत से 3-3.5 फीसदी कम दाम पर बेच रहे थे, जो अब 6.5-7 प्रे ति तक बढ़ गया है। मूंगफली तेल-तिलहन के दाम भी सुधार के साथ बंद हुए। तिलहन 6,450-6,825 रुपये प्रे ति क्विंटल, तेल 15,250 रुपये प्रे ति क्विंटल और साल्वेंट रिफाइंड 2,470-2,770 रुपये प्रे ति टिन पर बंद हुए। स्थानीय मांग बढ़ने के बावजूद हाजिर दाम एमएसपी से 10-12 फीसदी नीचे हैं। पामतेल और पामोलीन के भाव में मामूली सुधार हुआ। सीपीओ 11,275 रुपये, पामोलीन दिल्ली 13,125 रुपये और पामोलीन कांडला 12,100 रुपये प्रे ति क्विंटल पर बंद हुए। सरकार ने कच्चे पामतेल का आयात शुल्क घटाया और सोयाबीन डीगम तेल के आयात शुल्क में मामूली बढ़ोतरी की। विशेषज्ञों ने कहा कि आयात पर निर्भरता बढ़ने और हाजिर दाम एवं एमएसपी के बीच अंतर से किसानों और मिलों को नुकसान हो रहा है। बाजार में सुधार सरसों, मूंगफली और पामतेल में दिख रहा है, लेकिन सोयाबीन तिलहन की गिरावट और हाजिर दाम में अंतर चिंता का विषय बने हुए हैं।

कर्नाटक हाईकोर्ट : मामूली देरी या दस्तावेजों की कमी से मुआवजा हो सकता है रद्द

एमएसीटी में दावा दर्ज करने और मुआवजा पाने के लिए सावधानी जरूरी

नई दिल्ली

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल (एमएसीटी) के एक फैसले को सही ठहराते हुए स्पष्ट किया कि मामूली देरी, दस्तावेजों की कमी या सबूतों में खामियां भी सड़क दुर्घटना मुआवजे के हक को प्रभावित कर सकती हैं। मामले में, शिकायत दर्ज कराने में 24 दिन की देरी और आरोपी वाहन के शामिल होने को साबित न कर पाने के कारण एमएसीटी ने दावे को खारिज किया था। हाईकोर्ट ने भी इसे सही माना। एमएसीटी, मोटर व्हीकल एक्ट, 1988 की धारा 165 के तहत स्थापित है और यह मृत्यु, चोट या तीसरे पक्ष की संपत्ति को हुए नुकसान के मामलों में मुआवजा प्रदान करता है। यह सामान्य सिविल कोर्ट की लंबी प्रक्रिया नहीं अपनाता और धारा 168 के तहत संक्षिप्त प्रक्रिया में जांच कर फैसला सुनाता है। दावा दर्ज करने के लिए आवेदन में दुर्घटना का पूरा विवरण, चोट या नुकसान और मुआवजे की मांग लिखना आवश्यक है। इसे पीड़ित, मृतक के कानूनी प्रतिनिधि, संपत्ति के मालिक या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दाखिल किया जा सकता है। दावा उस एमएसीटी में दाखिल किया जा सकता है, जहां दावेदार या आरोपी का निवास या व्यवसाय है। आम तौर पर यह दावे दुर्घटना के 6 महीने के भीतर दाखिल किए जाते हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में इस सीमा को चुनौती दी गई है। मुआवजा तय करने में उम्र, आय, कमाई की क्षमता, भविष्य की आय के नुकसान, मेडिकल बिल, लंबी अवधि के इलाज की जरूरत और आश्रितों की निर्भरता जैसे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। दर्द और तकलीफ जैसी गैर-आर्थिक क्षतियां भी मुआवजे में शामिल होती हैं। विशेषज्ञ कहते हैं कि मजबूत दावा करने के लिए तुरंत एफआईआर दर्ज कराना, दुर्घटना स्थल से सबूत जुटाना, इलाज कराना और एमएलसी दर्ज कराना जरूरी है। देरी या दस्तावेजों में खामियां मामले को कमजोर कर सकती हैं, जैसा कि कर्नाटक हाईकोर्ट के हालिया फैसले में देखा गया।

1 दिसंबर से बदल जाएंगे कई नियम, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

सीएनजी-पीएनजी, एलपीजी, बैंकिंग, पेंशन और टैक्स से जुड़े नियम किए गए संशोधित

मुंबई

दिसंबर की शुरुआत के साथ ही कई बड़े ओ र्थिक और प्रशासे निक बदलाव लागू हो रहे हैं, जिनका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पडने वाला है। हर महीने की तरह इस बार भी गैस, बैंकिंग, पेंशन और टैक्स से जुड़े नियमों में संशोधन किए गए हैं। आइए जानते हैं 1 दिसंबर से क्या-क्या बदलने वाला है।

1. सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में संभावित बदलाव- ऑयल कंपनियां हर महीने सीएनजी, पीएनजी और जेट फ्यूल के दाम में संशोधन करती हैं। 1 दिसंबर को भी नई दरें जारी हो सकती हैं। कीमतों में बढ़ोतरी या कमी का असर सीधे घरेलू बजट पर पड़ेगा, खासकर उन परिवारों पर जो पीएनजी गैस से खाना पकाते हैं या सीएनजी वाहनों का उपयोग करते हैं।

2. एलपीजी सिलेंडर की कीमतें भी होंगी अपडेट- सरकार हर महीने घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के रेट में बदलाव करती है।

नवंबर में दिल्ली में 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 5 रुपए की कमी की गई थी। दिसंबर में फिर से नई कीमतें जारी की जाएंगी, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और आम उपभोक्ताओं का खर्च प्रभावित होगा।

3. पेंशनरों के लिए जरूरी निर्देश- पेंशन प्राप्त करने वाले बुजुर्गों के लिए दिसंबर बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने सभी पेंशनरों को 30 नवंबर या दिसंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के निर्देश दिए हैं। समय पर प्रमाण पत्र जमा न करने पर जनवरी से पेंशन रोक दी जाएगी। अच्छी बात है कि यह प्रक्रिया अब ऑनलाइन भी पूरी की जा सकती है।

4. ऑनलाइन बैंकिंग और कार्ड नियमों में बदलाव- 1 दिसंबर से कई बैंक ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, क्रेडिट व डेबिट कार्ड से जुड़े नियम अपडेट कर रहे हैं। कुछ बैंकों में सुरक्षा सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, वहीं कार्ड चार्ज और ट्रांजैक्शन फीस में बदलाव संभव है। ग्राहकों को अपने बैंक के नोटिफिकेशन पर नजर बनाए रखना चाहिए।

5. टैक्स फाइलिंग की अंतिम तिथि और बैंक हॉलिडे- अक्टूबर महीने की टीडीएस फाइलिंग की आखिरी तारीख 30 नवंबर तय की गई है। वहीं दिसंबर में लगभग 18 दिन बैंक हॉलिडे रहेंगे, इसलिए किसी भी बैंकिंग कार्य की पहले से योजना बनाना जरूरी है।

एफपीआई ने नवंबर में घरेलू शेयर बाजार से 3,765 करोड़ निकाले

साल 2025 में अब तक एफपीआई ने शेयरों से कुल 1.43 लाख करोड़ रुपये से अधिक निकाले

नई दिल्ली

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) नवंबर 2025 में भारतीय शेयर बाजार में फिर से बिकवाल बन गए हैं। अक्टूबर में 14,610 करोड़ रुपये के निवेश के बाद, विदेशी निवेशकों ने इस महीने शेयरों से 3,765 करोड़ रुपये निकाले। जुलाई से नवंबर तक एफपीआई का रुख अस्थिर रहा; जुलाई में 17,700 करोड़ रुपये, अगस्त में 34,990 करोड़ रुपये और सितंबर में 23,885 करोड़ रुपये की निकासी हुई थी। विशेषज्ञों के अनुसार नवंबर में बिकवाल बनने के कारण वैश्विक और घरेलू दोनों कारकों से जुड़े हैं। बाजार के विशेषज्ञों के मुतो बिक अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर नीति में अनिश्चितता, डॉलर में मजबूती और उभरते बाजारों में जोखिम लेने की क्षमता कम होना एफपीआई के सतर्क रुख की वजह बने। भू-राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव भी इसके पीछे हैं। उन्होंने कहा कि वैश्विक जोखिम से बचने की धारणा और प्रौद्योगिकी, उपभोक्ता सेवाओं एवं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के शेयरों में उतार-चढ़ाव मुख्य कारण हैं। एफपीआई का प्रवाह बदलने योग्य है, क्योंकि कुछ दिन खरीदार और कुछ दिन बिकवाल रहने का रुझान रहा है। साल 2025 में अब तक

एफपीआई ने शेयरों से कुल 1.43 लाख करोड़ रुपये से अधिक निकाले हैं। इसी दौरान, ऋण बाजार में निवेश 8,114 करोड़ रुपये का रहा, जबकि स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग से 5,053 करोड़ रुपये की निकासी हुई।

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

विराट कोहली ने रचा इतिहास: एक फॉर्मेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बने

रांची (एजेंसी)। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने एक बार फिर दबाव में शानदार प्रदर्शन करते हुए रविवार को रांची में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले ODI में अपना 52वां एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ दिया। यह शतक पुरुषों के क्रिकेट में 7000वां अंतर्राष्ट्रीय शतक भी है।

भारत ने सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा (51 गेंदों पर 57 रन) को एक शानदार अर्धशतक के बाद खो दिया था। रोहित-कोहली की जोड़ी ने 109 गेंदों पर 136 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिसने भारत के लिए मजबूत आधार तैयार किया। रोहित ने अपनी पारी में तीन छक्के भी लगाए।

रोहित के आउट होने के बाद, भारत की पारी थोड़ी लड़खड़ाई, जब रुतुराज गायकवाड़ और वाशिंगटन सुंदर सस्ते में आउट हो गए। रन रेट धीमा हुआ और साउथ अफ्रीका ने वापसी की कोशिश की।

हालांकि, कोहली अडिग रहे। उन्होंने चुपचाप शुरुआत की, लेकिन फिर जरूरत पड़ने पर गियर बदला और एक-एक ईंट से

अपनी पारी को बनाया। यह शतक 38वें ओवर में आया, जब उन्होंने ऑलराउंडर मार्को जेनसन की गेंद को बेहतरीन तरीके से थर्ड मैन के ऊपर से गाइड किया।

गेंद बाउंड्री के पार चली गई और कोहली ने हवा में मुक्का मारते हुए ज़ोरदार जश्न मनाया। दूसरे छोर पर, केएल राहुल ने शांत रहकर स्ट्राइक रोटेट की और कोहली को चार्ज लेने दिया। ओवर बाकी रहने और बैटिंग लाइनअप में गहराई होने के साथ, भारत 300 से अधिक रन बनाने की अच्छी स्थिति में दिख रहा है।

रोहित और विराट सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली भारतीय जोड़ी बनी, तेंदुलकर और द्रविड़ को पीछे छोड़ा

रांची । भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाजों रोहित शर्मा और विराट कोहली ने यहां दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय में उतरने ही एक अहम रिकार्ड अपने नाम कर लिया है। अब विराट और रोहित की जोड़ी भारतीय टीम की ओर से सबसे अधिक मैच खेलने वाली जोड़ी बन गयी है। इससे पहले ये रिकार्ड सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की जोड़ी के नाम था। अब रोहित और विराट ने एक साथ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 392 मैच खेले हैं। यह संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा खेले गए मैच हैं। वहीं सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ की जोड़ी ने 391 मैच खेले हैं। वहीं सबसे अधिक मैच खेलने वाली तीसरी जोड़ी राहुल द्रविड़ और गांगुली की है। इस जोड़ी ने 369 मैच खेले हैं। इस मैच से भारतीय प्रशंसकों को रोहित और विराट की जोड़ी को लंबे समय बाद एक साथ घरेलू मैदान पर खेलते हुए देखने का अवसर मिला है। रोहित और विराटने भारत के लिए एक साथ अपना पहला मैच 18 अगस्त 2008 को खेला था। तब से लेकर इन दोनों ने जमकर रन बनाते हुए एक साथ मिलकर टीम इंडिया को कई मैच जिताए। येसीरीज इन दोनो का ही भविष्य तय करेगी।, टेस्ट और टी20 से रोहित-कोहली के संन्यास लेने से टीम प्रबंधन उन्हें अगले विश्व कप के लिए दावेदार नहीं मान रहा था, मगर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इन दोनो ने ही जमकर रन बनाकर अपनी दांवेदारी पेश की थी। अब देखना है कि दक्षिण अफीका के खिलाफ ये कितने सफल रहते हैं।

रोहित शर्मा वनडे में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बने, दिग्गज पाकिस्तानी खिलाड़ी को पीछे छोड़ा

नई दिल्ली (एजेंसी)। स्पोर्ट्स डेस्क -टीम इंडिया के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। रोहित अब वनडे क्रिकेट में 352 छक्कों के साथ इस फॉर्मेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। रोहित को इस मैच से पहले ये रिकॉर्ड बनाने के लिए 3 छक्कों की जरूरत थी। रोहित ने इस मामले में पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी (351) को पीछे छोड़ दिया है जो इससे पहले वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के (351) मारने वाले खिलाड़ी थे।

रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 136 रन की साझेदारी की। रोहित ने अपनी पारी के दौरान 51 गेंदों में 57 रन बनाए जिसमें 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे।

ODI में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले टॉप 5 खिलाड़ी

रोहित शर्मा - 352
शाहिद अफरीदी - 351
क्रिस गेल - 331
सनथ जयसूर्या - 270
महेंद्र सिंह धोनी - 229

सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी : अभिषेक ने 12 गेंदों मे ही लगाया अर्धशतक

-सबसे तेज पचास रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बने

हैदराबाद (एजेंसी)। पंजाब की ओर से खेलते हुए बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 12 गेंदों पर ही अर्धशतक लगा दिया। अभिषेक ने 425.00 के स्ट्राइक रेट से रन बनाये हैं। इस युवा बल्लेबाज ने हैदराबाद में बंगाल के खिलाफ एलीट ग्रुप सी के मुकाबले में 12 गेंद में 5 चौके और 5 छक्के लगाकर सबको हैरान कर दिया।

पंजाब कप्तानी करते हुए अभिषेक ने बंगाल के गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। पहले दो मैचों में वह रन नहीं बना पाये थे पर इस मैच में उन्होंने कोई गलती नहीं की। इस मैच में उन्होंने मोहम्मद शमी की गेंदों पर भी जमकर शॉट लगाये। अभिषेक का 12 गेंदों में लगाया अर्धशतक पुरुष टी20 क्रिकेट में संयुक्त रूप से तीसरा व किसी भारतीय द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है। प्रभसिमरन सिंह के साथ पारी की शुरुआत करते हुए अभिषेक ने शमी और आकाश दीप की गेंदों को जमकर पीटा। उन्होंने साक्षम चौधरी और वृत्तिक चटर्जी के खिलाफ भी तेजी से रन बनाये।

टी20 में सबसे तेज अर्धशतक नेपाल के दिपेंद्र सिंह ऐरी ने सितंबर 2023 में हांगझो एशियन गेम्स के दौरान मंगोलिया के खिलाफ 10 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। वहीं भारत के अशुतोष शर्मा दूसरे नंबर पर हैं, जिन्होंने 2023-24 सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ रेलवे की ओर से खेलते हुए 11 गेंदों में ही पचास रन बना दिये। अब अभिषेक तीसरे नंबर पर आ गये हैं।

चयनकर्ता प्रमुख अजीत अगरकर घरेलू ड्यूटी पर अहमदाबाद में तैनात

अहमदाबाद (एजेंसी)। चयनकर्ता प्रमुख अजीत अगरकर 26 नवंबर से घरेलू ड्यूटी पर अहमदाबाद में तैनात हैं, जबकि भारतीय क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से घरेलू टेस्ट हार से अभी भी जूझ रहा है। सेलेक्टर्स के चेयरमैन, जिनकी अक्सर घरेलू सर्किट से ज़्यादा इंटरनेशनल गेम को प्राथमिकता देने के लिए आलोचना की जाती है, नेशनल टी20 चैंपियनशिप के ग्रुप डी मैचों की देखरेख कर रहे हैं जो अभी कई शहरों में फैले हुए हैं।

अगरकर की अगुवाई वाला पैनल घरेलू क्रिकेट से दूर रहने, खासकर व्हाइट-बॉल रिटर्न के आधार पर टेस्ट खिलाड़ियों को चुनने और स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों के बजाय ऑलराउंडरों को तरजीह देने के लिए जांच के दायरे में है। साई सुदर्शन और नीतीश रेड्डी के चयन ने ध्यान खींचा है, जबकि सरफराज खान, अभिमन्यु ईश्वरन और करुण नायर को बाहर रखने पर बहस जारी है। हालांकि चयन पांच सदस्यों वाली कमेटी का सामूहिक फैसला है, लेकिन अगरकर की सबसे ज्यादा आलोचना विदेशी दौरों और इंटरनेशनल मैचों में उनकी लगातार मौजूदगी के कारण हुई है।

यह साफ नहीं है कि टेस्ट हार के बाद उनका मौजूदा घरेलू कार्यकाल बीसीसीआई के किसी निर्देश से जुड़ा है या नहीं, लेकिन अगरकर को पिछले कुछ दिनों में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में देखा गया है। दूसरे चयनकर्ताओं में, प्रज्ञान ओझा रविवार (30 नवंबर) से दक्षिण अफ्रीका में शुरू होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम के साथ यात्रा करने वाले हैं, जबकि एसएस दास (कोलकाता), आरपी सिंह (लखनऊ) और अजय रात्रा (हैदराबाद) सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी ड्यूटी पर हैं।

टेस्ट सीरीज में हार के बाद रेड-बॉल क्रिकेट को लेकर भी बड़ी चर्चाएं शुरू हो गई हैं जिसमें यह भी शामिल है कि क्या इस फॉर्मेट से हटने वाले सीनियर खिलाड़ियों से दोबारा सोचने के लिए कहा जा सकता है। इस बात का कोई संकेत नहीं है कि विराट कोहली से संपर्क किया गया है, लेकिन यह विचार फैलने लगा है। किसी भी औपचारिक कदम की कोई निश्चितता नहीं है, हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि हाल ही में रिटायर हुए कम से कम एक खिलाड़ी दोबारा सोचने के लिए तैयार हो सकता है।

कई फ्रेंचाइजी स्काउट्स भी सैय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफी वेन्यू पर पहुंच गए हैं, जिसमें जॉन राइट - भारत के पूर्व कोच और लंबे समय से मुंबई इंडियंस के स्काउट, अहमदाबाद के प्रमुख नामों में से हैं। वरुण एरॉन, पार्थिव पटेल, किरण मोरे और विजय भारद्वाज भी मौजूद हैं। राइट, जो सालों से मुंबई इंडियंस के लिए स्काउट रहे हैं और जिन्हें जसप्रीत बुमराह को खोजने का श्रेय दिया जाता है, 16 दिसंबर को आईपीएल ऑक्शन से पहले एक्शन पर नजर रख रहे हैं। अहमदाबाद ने दूसरे सेंटर्स की तुलना में ज़्यादा ध्यान खींचा है, जहां झारखंड, तमिलनाडु, कर्नाटक, सौराष्ट्र, उत्तराखंड, दिल्ली और त्रिपुरा की टीमें अभी नरेंद्र मोदी स्टेडियम के मैदान में खेल रही हैं।

भारत अंडर-19 और अफगानिस्तान अंडर-19 के बीच त्रिकोणीय श्रृंखला का फाइनल रद्द

बेंगलुरु । भारत अंडर-19 और अफगानिस्तान अंडर-19 के बीच एकदिवसीय त्रिकोणीय श्रृंखला का फाइनल मैच खराब मौसम की वजह से रविवार को यहां रद्द हो गया। भारत अंडर-19 टीम 19 ओवर में पांच विकेट पर 79 रन बनाकर जूझ रही थी जब बारिश और खराब रोशनी की वजह से खेल रोकना पड़ा जो दोबारा शुरू नहीं हो पाया। तेज गेंदबाज अब्दुल अजीज ने कप्तान विहान मल्होत्रा ??और वंश आचार्य के विकेट लेकर अफगानिस्तान को शुरुआती सफलताएं दिलाईं जिससे भारत का स्कोर चार विकेट पर 24 रन हो गया। निष्क चौहान (नाबाद 28) और अभिज्ञान कुंडू (27) ने पांचवें विकेट के लिए 51 रन जोड़कर विकेटों के पतझड़ पर विराम लगाया लेकिन इसके बाद बारिश के कारण खेल रोकना पड़ा और अंतत- मैच रद्द हो गया।

हरमनप्रीत और युवराज सिंह के नाम के स्टैंड बनाएगी पीसीए

चंडीगढ़ । अब पूर्व ऑलरांउडर युवराज सिंह और भारतीय महिला किकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर के नाम के स्टैंड मोहाली में मुल्लांपुर स्थित महाराजा यादवेंद्र सिंह क्रिकेट स्टेडियम में बनेंगे। ये घोषणा पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन (पीसीए) ने की है। इसके अलावा, हरमनप्रीत के साथ ही अमनजोर कौर को इनामी राशि भी दी जाएगी। पीसीए के कार्यवाहक सचिव सिद्धार्थ शर्मा ने कहा, इन खिलाड़ियों को विश्वकप जीतने के लिए सम्मानित किया जा रहा है। साथ ही कहा कि हमने उनके नाम पर एक स्टैंड की घोषणा की है। 11 दिसंबर को भारत-दक्षिण अफ्रीका मैच में युवराज और हरमनप्रीत के नाम के स्टैंड का उद्घाटन होगा। यह स्टैंड न्यू मुल्लापुर में नए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में बनेगा। यह उनकी उपलब्धि के लिए हमारी ओर से एक छोटी सी भेंट है। सिद्धार्थ के अनुसार इन महिला खिलाड़ियों को देखकर ही युवा लड़कियां भी इस खेल से जुड़ेंगी। उन्होंने कहा, महिला क्रिकेट में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना और जेमिमा रोड्रिगेज जैसी खिलाड़ियों को देखकर ही युवा सामने आएंगी। साथ ही कहा कि जब युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी, तभी महिला क्रिकेट आगे बढ़ेगा। हरमनप्रीत की कप्तानी में भारतीय टीम ने महिला विश्व कप 2025 के फाइनल मैच में दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर खिताब जीता था। इस मुकाबले में भारतीय टीम ने 50 ओवरों में 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए। इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीकी टीम 45.3 ओवरों में महज 246 रन ही बना पायी। वहीं युवराज सिंह ने भारत को टी20 विश्व कप 2007 और एकदिवसीय विश्व कप 2011 का खिताब जिताने में अहम भूमिका निभाई।

हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप : भारत की ओमान पर 17-0 से शानदार जीत, क्वार्टर-फाइनल में जगह बनाने के करीब

चेन्नई (एजेंसी)। भारत ने चेन्नई के एग्मोर में मेयर राधाकृष्णन हॉकी स्टेडियम में अपने दूसरे पूल बी मैच में ओमान को 17-0 से हराकर पुरुषों के हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में अपनी लगातार दूसरी जीत हासिल की। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने शुक्रवार को टूर्नामेंट के अपने पहले मैच में चिली को 7-0 से हराया था। अर्शदीप सिंह (4', 33', 40'), मनमीत सिंह (17', 26', 36') और दिलराज सिंह (29', 32', 58') ने हैट्रिक बनाई, जबकि अजीत यादवल (34', 47'), गुरजोत सिंह (39', 45') और लुवांग थोनाओजम इंगालेम्बा (43', 50') ने दो-दो गोल किए।अ नमोल एक्का (29') और शारदा नंद तिवारी (55') ने मैच के बाकी दो गोल किए।

अर्शदीप ने चौथे मिनट में गोल किया, लेकिन यह पहले क्वार्टर का एकमात्र गोल साबित हुआ, क्योंकि ओमान ने अपनी

किस्मत और आखिरी समय में कुछ अच्छे डिफेंस के दम पर स्कोर 1-0 पर बनाए रखा। लेकिन, दूसरे पीरियड में मनमीत सिंह के दो गोल से भारत ने बढ़त बना ली, जिसके बाद दिलराज सिंह और अनमोल एक्का ने हाफ-टाइम तक भारत को 5-0 से आगे कर दिया। भारत ने तीसरे क्वार्टर में जोरदार वापसी की, जिसमें मेज़बान टीम ने मेहमान टीम पर आठ गोल किए, जिसमें मनमीत और अर्शदीप ने अपनी-अपनी हैट्रिक पूरी कीं।

भारत ने आखिरी क्वार्टर में भी चार और गोल करके अच्छा प्रदर्शन किया, जब दिलराज सिंह ने 58वें मिनट में अपने हैट्रिक गोल से शानदार स्कोरलाइन को खत्म किया। भारत के पांच गोल पेनल्टी कॉर्नर से आए, जबकि शारदा नंद तिवारी ने पेनल्टी स्ट्रोक को गोल में बदलकर स्कोरशीट में अपना नाम दर्ज कराया। बाकी 11 गोल ओपन प्ले से आए।

इस जीत की वजह से, भारत अभी चल रहे जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के ग्रुप बी में बेहतर गोल डिफरेंस के आधार पर टॉप पर है। इस नतीजे का यह भी मतलब है कि अगर भारत मंगलवार को अपने आखिरी ग्रुप बी मैच में स्विट्जरलैंड से हार से बचता है, तो वह पूल विनर के तौर पर सीधे मेन्स हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप 2025 के क्वार्टर-फाइनल में पहुंच जाएगा। अगर भारत स्विट्जरलैंड से हार जाता है जिसने भी दो मैचों में दो जीत हासिल की हैं, तो उसे क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालीफाई करने के लिए छह रनर-अप टीमों में टॉप दो टीमों में शामिल होना होगा।

MLS CUP: मेस्सी की इंटर मियामी टीम ने न्यूयॉर्क सिटी FC को 5-1 से हराकर फाइनल में एंट्री की

फोर्ट लाउडरडेल। लियोनेल मेस्सी की टीम इंटर मियामी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए न्यूयॉर्क सिटी स्नष्ट को 5-1 से हराकर ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस खिताब जीत लिया और इसके साथ ही एमएलएस कप फाइनल में जगह पक्की कर ली। इस जीत के बाद मेस्सी का एक और बड़े खिताब के लिए खेलना लगभग तय हो गया है। इंटर मियामी की जीत के हीरो रहे मेस्सी के अर्जेंटीनी साथी तादेओ अलेंदे, जिन्होंने बेहतरीन हैट्रिक जमाई। वहीं, जॉर्डी अल्बा और सर्जियो बुस्केट्स ने भी एक-एक गोल दागा। मेस्सी के लिए यह मैच व्यक्तिगत रूप से खास नहीं रहा, लेकिन उन्होंने शुरुआती दो गोल में महत्वपूर्ण असिस्ट दिए। यह क्लब और देश के लिए मिलाकर मेस्सी के करियर का 405वां असिस्ट था, जो फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक माने जाते हैं। इंटर मियामी अब एमएलएस कप फाइनल में वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस के विजेता—सैन डिएगो या वैंकूवर की मेजबानी आगामी शनिवार को करेगी।

इमोशनल कोच होना हमेशा फायदेमंद नहीं, गौतम गंभीर पर डिविलियर्स का बड़ा बयान

नई दिल्ली (एजेंसी)। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज में 0-2 की शर्मनाक हार के बाद भारतीय टीम और मुख्य कोच गौतम गंभीर लगातार आलोचना के केंद्र में हैं। सोशल मीडिया से लेकर क्रिकेट विश्लेषकों तक, गंभीर पर भारत के टेस्ट क्रिकेट को गलत दिशा में ले जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। उन पर लगातार प्रयोग करने, बैटिंग ऑर्डर में अनिश्चित बदलाव, स्पेशलिस्ट खिलाड़ियों को नज़रअंदाज़ करने और ऑलराउंडरों को लेकर अतिशय लगाव दिखाने की बातें तेजी से सामने आ रही हैं। हालांकि गंभीर साफ कह चुके हैं कि टीम ट्रांजिशन के दौर में है और बदलाव का ये ही सही समय होता है, चाहे उसे लेकर कितनी भी आलोचना क्यों न झेलनी पड़े। इसी बीच दक्षिण अफ्रीका के पूर्व महान बल्लेबाज एबी डिविलियर्स ने एक दिलचस्प और महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। रविचंद्रन अश्विन के यूट्यूब चैनल से बातचीत में डिविलियर्स ने कहा कि टीम का कोच बहुत ज्यादा इमोशनल हो, तो यह हमेशा सकारात्मक साबित नहीं होता। उन्होंने कहा, 'मैं गौतम गंभीर को एक बेहद भावुक खिलाड़ी के रूप में जानता आया हूं। अगर ड्रेसिंग रूम में भी वही भावुकता हावी रहती है, तो आमतौर पर इमोशनल कोच का होना अच्छी बात नहीं माना जाता।'

डिविलियर्स और गंभीर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में एक साथ लंबा वक्त बिताया है और कई बार एक-दूसरे के खिलाफ बड़े मुकाबले खेले हैं। आईपीएल में भी दोनों कई साल प्रतिद्वंद्वी रहे। इन्हीं अनुभवों की वजह से डिविलियर्स गंभीर की कोचिंग स्टाइल को समझने की कोशिश करते दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भावुक खिलाड़ी होना जरूरी नहीं कि वही शख्स भावुक कोच भी हो। डिविलियर्स ने कहा, 'हर खिलाड़ी की जरूरत अलग होती है। कुछ लोग ऐसे कोच के साथ ज्यादा सहज महसूस करते हैं जो खुद महान खिलाड़ी रहा हो, जबकि कुछ ऐसे कोच के साथ बेहतर खेलते हैं जिनके पास वर्षों का कोचिंग अनुभव हो, भले उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर न खेला हो।' उन्होंने बताया कि उन्हें गैरी कर्स्टन जैसे शांत और संतुलित कोच के तहत खेलना बेहद पसंद था, और यह उनके प्रदर्शन के लिए फायदेमंद साबित हुआ। भारत में टेस्ट सीरीज की हार के बाद अगले साल गंभीर के लिए बड़ा इम्तिहान होगा और टीम के प्रदर्शन से ही तय होगा कि उनका प्रयोगात्मक दृष्टिकोण सही दिशा में है या नहीं। आलोचनाओं के बावजूद डिविलियर्स ने संकेत दिया कि नए बदलावों को समय दिया जाना चाहिए, क्योंकि हर टीम कभी न कभी बदलाव के दौर से गुजरती है।

डब्ल्यूबीबीएल 2025 : पॉइंट्स टेबल में शीर्ष पर पहुंची मेलबर्न स्टार्स

मेलबर्न । विमेंस बिग बैश लीग (डब्ल्यूबीबीएल) 2025 के 28वें मुकाबले में शनिवार को मेलबर्न स्टार्स ने जंक्शन ओवल में खेले गए मैच में मेलबर्न रेनेगेड्स पर 45 रन की शानदार जीत दर्ज की। इस महत्वपूर्ण जीत के साथ मेलबर्न स्टार्स ने प्वाइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया है। स्टार्स ने अब तक खेले गए 7 मुकाबलों में से 5 में जीत दर्ज की है, जबकि एक मैच में हार का सामना करना पड़ा और एक मुकाबला बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। दूसरी ओर मेलबर्न रेनेगेड्स ने अब तक 8 मैच खेले हैं, जिसमें से टीम ने 4 में जीत हासिल की है और 4 में उसे हार झेलनी पड़ी है। अंक तालिका में रेनेगेड्स वर्तमान में तीसरे स्थान पर है। टॉस गंवाकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी मेलबर्न स्टार्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने महज 14 रन पर रिस मैककेना का विकेट गंवा दिया, जो सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हुईं। शुरुआती झटके के बाद मेग लैनिंग और एमी जोन्स ने मिलकर टीम को संभाला और दूसरे विकेट के लिए 51 गेंदों में 62 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। एमी जोन्स ने 33 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 43 रन की उपयोगी पारी खेली। इसके बाद कप्तान एनाबेल सदरलैंड ने लैनिंग का साथ देते हुए तीसरे विकेट के लिए 43 गेंदों में 70 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। सदरलैंड ने 16 गेंदों में 27 रन का योगदान दिया, जबकि मेग लैनिंग अंत तक नाबाद रहीं और 58 गेंदों में 1 छक्का और 7 चौकों की मदद से शानदार 73 रन बनाए। निर्धारित 20 ओवर में मेलबर्न स्टार्स ने 5 विकेट पर 160 रन का प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया। रेनेगेड्स की ओर से मिली इलिंगवर्थ ने सबसे ज्यादा 3 विकेट चटकाए, जबकि जॉर्जिया वेयरहैम ने 2 विकेट अपने नाम किए। लक्ष्य का पीछा करते हुए मेलबर्न रेनेगेड्स की टीम कभी भी लय में दिखाई नहीं दी और 16.3 ओवरों में 115 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। टीम के लिए डिएंड्रा डॉटिन और निकोल फाल्टम ने सर्वाधिक 23-23 रन बनाए, जबकि इसी वोंग ने 20 रन का योगदान दिया। मेलबर्न स्टार्स के गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें मैसी गिब्सन ने 3 विकेट चटकाए और किम गार्थ ने 2 सफलताएं हासिल कीं।

रसेल अब आईपीएल में नहीं खेलेंगे, सहयोगी स्टाफ के तौर पर उतरेंगे

जमैका (एजेंसी)। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर आंद्रे रसेल अब आईपीएल में खेलते हुए नहीं दिखेंगे। इसका कारण है कि रसेल ने आईपीएल से संन्यास ले लिय है।

रसेल के इस फैसल से उनकी टीम कोलकाता नाइटराइडर्स (केकेआर) के प्रशंसक हैरान हैं। रसेल अचानक ही संन्यास ले लेंगे। इसका अंदेशा उन्हें नहीं था। वह अभी विश्वभर की टी20 लीग्स में अपने प्रदर्शन से छाये हुए हैं। इस कारण आईपीएल में भी उनकी अच्छी मांग हैं। रसेल ने यह फैसला केकेआर द्वारा उन्हें आईपीएल 2026 की नीलामी से पहले ही रिलीज करने के बाद लिया। रसेल ने आईपीएल को अलविदा कह दिया है पर कहा है कि वह सहयोगी स्टाफ के तौर पर उतरेंगे।

रसेल ने कहा कि वह केकेआर के साथ बने रहेंगे। वह आईपीएल 2026 में कोलकाता नाइट राइडर्स के सहयोगी स्टाफ के रूप में टीम के साथ बने रहेंगे।

रसेल ने अपने संन्यास की घोषणा करते हुए लिखा, 'ढ्ढक्रसे संन्यास ले रहा हूं। साथ ही कहा कि इसमें शानदार सफर रहा है। सीज़न की यादें, और केकेआर परिवार से काफी प्यार मिला। मैं दुनिया भर की हर दूसरी लीग में छक्के मारता रहूंगा और विकेट लेता रहूंगा। और सबसे अच्छी बात? मैं घर नहीं छोड़ रहा हूं। इस बार मैं नई भूमिका में नजर आउंगा।।'

रसेल ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत केकेआर नहीं बल्कि दिल्ली कैपिटल्स के साथ 2012 में की थी। दो सत्र दिल्ली से खेलने के बाद वह 2014 में केकेआर के साथ जुड़े और अपने पहले ही सीजन में उन्होंने टीम को विजेता बनाया। साल 2014 के बाद 2025 तक वह लगातार 12 साल कोलकाता की टीम का हिस्सा रहे। रसेल ने आईपीएल में कुल 140 मैच खेले जिसमें उन्होंने 2651 रन बनाने के साथ-साथ 123 विकेट लिए। ऐसे में एक खिलाड़ी के तौर पर लीग में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है।

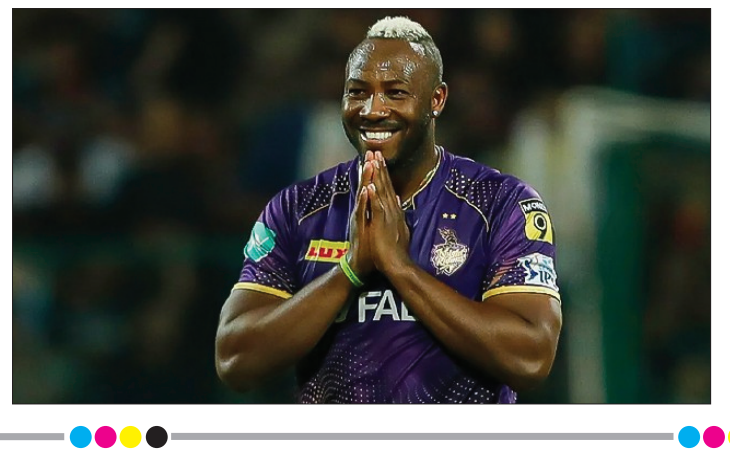

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संक्षिप्त समाचार

गिनी बिसाऊ में इलिडियो विएरा नए प्रधानमंत्री

बिसाऊ, एजेंसी। पश्चिमी अफ्रीकी देश- गिनी-बिसाऊ में हालिया चुनाव के कुछ दिनों के भीतर ही तख्तापलट के बाद सेना ने शुक्रवार को इलिडियो विएरा ते को नया प्रधानमंत्री नियुक्त नियुक्त किया है। विएरा ते हटाए गए राष्ट्रपति उमारो सिस्सोको एम्बालो के करीबी सहयोगी हैं। उन्होंने रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव के दौरान उनके कैंपेन डायरेक्टर के तौर पर काम किया था। देश के नए मिलिट्री लीडर जनरल होर्ता इंटा-आ ने एक आदेश कर उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त करने की घोषणा की है। गौरतलब है कि, बुधवार को राष्ट्रीय चुनावों के तीन दिन बाद सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। अपदस्थ राष्ट्रपति उमारो सिस्सोको एम्बालो पड़ोसी सेनेगल चले गए हैं। इस बीच, विपक्ष ने कहा कि चुनाव में हार से बचने के लिए एम्बालो ने तख्तापलट की साजिश रची थी। सेना के जरिये कर्फ्यू हटाए जाने के बाद राजधानी बिसाऊ में शांति लौट आई है। लोग और गाड़ियां शहर की सड़कों पर घूम रही हैं। मुख्य स्टॉक एक्सचेंज और बाहरी जिलों के बाजार, बैंक भी फिर से खुल गए हैं। गिनी-बिसाऊ दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है।

ब्रिटेन में कुल प्रवासन घटकर 2.04 लाख पर पहुंचा

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन में कुल प्रवासन जून 2025 तक तेजी से घटकर 2,04,000 रह गया है। देश के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (ओएनएस) के अनुसार यह गिरावट मुख्यत: नए अप्रवासियों में कमी और देश छोड़ने वालों की संख्या में हल्की बढ़ोतरी के कारण हुई। जून 2023 में कुल प्रवासन 9.06 लाख के उच्च स्तर पर था। रिपोर्ट में बताया गया कि जून 2025 तक ईयू और यूके दोनों नागरिक समूहों में शुद्ध बाहर जाने वालों की संख्या अधिक रही। इनमें देश छोड़ने वाले अधिकांश ब्रिटिश नागरिक 35 वर्ष से कम आयु के थे।

गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ वापस ली शिकायत

लंदन, एजेंसी। गूगल ने माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड व्यवसाय के खिलाफ दायर अपनी यूरोपीय यूनियन से प्रतिस्पर्धा रोधी शिकायत वापस ले ली है। यह कदम ऐसे समय आया है, जब यूरोपीय आयोग ने हाल ही में क्लाउड सेक्टर में माइक्रोसॉफ्ट की जांच शुरू की है। गूगल ने पिछले साल आरोप लगाया था कि माइक्रोसॉफ्ट अपने एज्यूर प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को बांधकर प्रतिस्पर्धा घटा रहा है। क्लाउड बाजार में अमेजन 30 फीसदी हिस्सेदारी के साथ शीर्ष पर है, जबकि माइक्रोसॉफ्ट 20 फीसदी और गूगल 13 फीसदी पर है।

अफगान सरकार की ईंधन की खपत कम करने की अपील

काबुल , एजेंसी। अफगानिस्तान के काबुल में नगर पालिका ने सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए निवासियों से ईंधन की खपत कम करने की अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि छोटे घरों में चलने वाले स्टोव व चूल्हे इसके प्रमुख स्रोत हैं। शहर में प्रदूषण पिछले साल की तुलना में अधिक दर्ज किया गया है, जिससे लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। विशेषतौर से सुबह और शाम के समय धुआं व धूल आंखों व सांस लेने में परेशानी पैदा कर रहे हैं।

यूरोप और अमेरिका में बर्ड फ्लू के मामले बढ़े, 3 महीने में 1.6 करोड़ मुर्गियां मारी गई

बर्लिन, एजेंसी। यूरोप और उत्तरी अमेरिका में बर्ड फ्लू (हाईली पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा) तेजी से फैल रहा है। जंगली पक्षियों और मुर्गी फार्मों में तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका में 18 नवंबर तक 107 जगहों पर बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। बर्ड फ्लू के कारण सितंबर से अब तक अमेरिका और कनाडा में करीब 1 करोड़ 60 लाख मुर्गियां मारनी पड़ी हैं। सितंबर से नवंबर तक 26 यूरोपीय देशों में जंगली पक्षियों में 1,443 फ्लू के मामले दर्ज किए गए, जो पिछले साल से 4 गुना ज्यादा और 2016 के बाद सबसे अधिक है। जर्मनी में तीन साल में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं, फ्रांस ने अक्टूबर में ही पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया था।

श्रीलंका में चक्रवात 'दित्वाह' : राहत कार्यों के लिए कोलंबो पहुंची एनडीआरएफ टीमें, ऑपरेशन सागर बंधु जारी

कोलंबो, एजेंसी। श्रीलंका में चक्रवात 'दित्वाह' तबाही मचा रहा है। शनिवार को यह तूफान तमिलनाडु की तरफ बढ़ रहा है। चेन्नई के दक्षिण में चक्रवात दित्वाह 430 किलोमीटर की दूरी पर है। रविवार सुबह तक इसके उत्तरी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटवर्ती इलाकों में पहुंचने की आशंका है। बंगाल की खाड़ी के दक्षिण-पश्चिम में यह चक्रवात बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है।

पाकिस्तान की चाल नाकाम, ऑक्सफोर्ड में बहस से भागकर भारतीयों पर आरोप, खुली पोल

लंदन, एजेंसी। ब्रिटेन की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड में भारत और पाकिस्तान के प्रतिनिधियों के बीच होने वाली एक बहस रद्द कर दी गई है। इस बहस के रद्द होने का दुनिया के ज्यादातर लोगों को कोई पता नहीं चला। लेकिन झूठे पाकिस्तान को यह कहां बर्दाश्त था। भारत के खिलाफ मिली हर हार को अपनी जीत बनाकर पेश करने वाले पाकिस्तान ने यहाँ पर भी बहस से भागकर इसे जीत बनाने की कोशिश करनी शुरू कर दी। ब्रिटेन स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग ने ट्वीट करके दावा किया कि ऑक्सफोर्ड में होने वाली बहस से भारतीय प्रतिनिधि पीछे हट गए हैं। बाद में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वकील जे साईं दीपक ने पाकिस्तान के इस झूठ का सबूतों के साथ पर्दाफाश कर दिया। पाकिस्तानी उच्चायोग की तरफ से ट्वीट करके कहा गया कि ऑक्सफोर्ट यूनिवर्सिटी में 'भारत की पाकिस्तान नीति एक सुरक्षा नीति के रूप में बेची गई जनप्रिय रणनीति है।' नामक शीर्षक पर बहस होनी थी, लेकिन भारतीय वक्ता अंतिम समय पर इस बहस से पीछे हट गए। पाकिस्तानी उच्चायोग ने इस बहस के लिए भारत की तरफ से जिन वक्ताओं के नाम बताए उनमें पूर्व सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवाणे, सुब्रमण्यम स्वामी और राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का नाम था। वहीं, पाकिस्तान की तरफ से पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार, ब्रिटेन में पाकिस्तान के उच्चायुक्त मोहम्मद फैसल और पाकिस्तानी सेना के पूर्व जनरल जुबैर महमूद हयात शामिल थे।

जे साई दीपक ने खोली पोल : पाकिस्तान के ब्रिटेन स्थित हाईकमीशन द्वारा फैलाए जा रहा यह झूठ जब तक दुनिया तक पहुंचता उससे पहले भी भारतीय सुप्रीम कोर्ट के वकील जे साईं दीपक ने इसकी बखियां उधेड़ दीं। उन्होंने पाकिस्तानी दावों का खंडन सबूतों के साथ किया। उन्होंने कहा ऑक्सफोर्ड द्वारा भेजी गई अपनी भागीदारी की पुष्टि वाली ईमेल को भी साझा करते हुए लिका कि उनके साथ पूर्व सेना प्रमुख नरवाने और स्वामी भी भारतीय पक्ष की तरफ से वक्ता थे। उन्होंने लिखा, 'पाकिस्तानी लोग ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को भी गड़बड़ कर देते हैं और हमेशा की तरह इस बार भी वह सच बोलने की ताकत नहीं रखते। दीपक ने कहा, 'इस ईमेल के बाद यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया कि नरवाने और स्वामी इस कार्यक्रम में नहीं आ सकते हैं। उन्होंने मुझसे कोई नए नाम भेजने के लिए कहा। लेकिन जब तक मैं विकल्प भेज पाता उससे पहले ही मुझे बताया गया कि इस बहस के लिए सुहेल सेठ और राज्य सभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी से संपर्क किया गया है और उन्होंने शामिल होना स्वीकार किया है। मुझे लगा की ठीक है मामला खत्म हुआ। लेकिन इसके बाद मुझे बताया गया कि दोनों ने एक दम से नोटिस देने की वजह से इस कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया है। '

प्रियंका चतुर्वेदी ने भी की पुष्टि : प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सोशल मीडिया पर इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उन्हें जुलाई में ही इसका आमंत्रण मिल गया था लेकिन उसके बाद कोई संपर्क नहीं किया गया। इसलिए मैंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाल ही में एक दम उनका फोन आया। इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। दीपक अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इसके बाद भी अंतिम समय पर मैं लंदन पहुंच कर बहस में शामिल होने के लिए तैयार था। यहां पर उन्होंने मनु खजूरिया और पंडित सतीश शर्मा के साथ मिलकर एक टीम भी तैयार कर ली। लेकिन बहस के तीन घंटे पहले उन्हें बताया गया कि बहस रद्द कर दी गई है क्योंकि पाकिस्तानी दल लंदन पहुंचा ही नहीं है। दीपक ने लिखा, 'इस बात में मैं गुस्सा था, क्योंकि इसमें काफी मेहनत लगी थी।' इतना ही नहीं दीपक ने सबूत के तौर पर इस पूरी बहस के आयोजक मूसा हरराज की कॉल लॉग भी साझा की।

पाकिस्तान को दी चुनौती : इसके बाद दीपक ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए लिखा कि बाद में मुझे पता चला कि इस बहस के आयोजक मूसा हरराज, जिनके पिता पाकिस्तान में मंत्री हैं। उन्होंने इस पूरी झूठी कहानी को गढ़ा है। पाकिस्तान की टीम लंदन में ही मौजूद थी। लेकिन बहस नहीं करना चाहती थी। उन्होंने चुनौती देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान की टीम तैयारी के साथ है तो फिर बहस के लिए सामने आ जाए। उन्हें इसमें आतंकियों की तरह छिपने की जरूरत नहीं है। डिबेट से तीन घंटे पहले पाकिस्तानी स्पीकर के नहीं आने की जानकारी मिली इसके बाद साई दीपक खुद ब्रिटेन पहुंचे और आखिरी मौके पर ब्रिटेन में रहने वाले दो भारतीय मूल के स्पीकर मनु खजूरिया और पंडित सतीश शर्मा को टीम में शामिल कर लिया। यानी भारतीय टीम पूरी तरह तैयार थी।

मौत और तबाही लेकर आया चक्रवाती तूफान सेन्यार, इन देशों में मरने वालों का आंकड़ा 300 के पार

जकार्ता, एजेंसी। चक्रवाती तूफान सेन्यार ने कमजोर होने से पहले इंडोनेशिया और थाईलैंड जैसे देशों में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 300 तक पहुंच गया है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया है कि इंडोनेशिया के सुमात्रा आइलैंड पर अचानक आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 174 हो गई। वहीं दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। इस बीच शुक्रवार को दक्षिणी थाईलैंड में आई भारी बाढ़ में कम से कम 145 लोगों की मौत हो गई है। इंडोनेशिया की मौसम संबंधी एजेंसी ने बताया है कि चक्रवाती तूफान दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों को कई दिनों तक प्रभावित कर सकता है। एजेंसी के एक अधिकारी ने बताया कि मलक्का स्ट्रेट में बना ट्रॉपिकल साइक्लोन सेन्यार खराब मौसम की वजह बन रहा है। उन्होंने कहा है कि खराब मौसम संबंधी चेतावनी बढ़ा दी है। तूफान के बाद आए मूसलाधार बारिश और बाढ़ की वजह से नॉर्थ सुमात्रा प्रांत में 3,200 से ज़्यादा घर और इमारतें डूब गई हैं। हजारों लोगों को सरकारी राहत शिविरों में शिफ्ट किया गया है। वहीं वेस्ट सुमात्रा में, 17,000 से ज्यादा घर डूब गए, और लगभग 23,000 लोगों को टेम्परारी शेल्टर में ले जाया गया है। इस बीच खराब मौसम की वजह से बचाव कार्य में भी मुश्किलें आ रही हैं। नॉर्थ सुमात्रा रीजनल पुलिस के स्पोक्सपर्सन फेरी वुलंटुकन ने बताया है कि मिट्टी धंसने, बिजली ना होने और टेलीकम्युनिकेशन की बाधा की वजह से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में रुकावट आ रही है। थाईलैंड में भी बाढ़ ने भीषण तबाही मचाई है। पानी कम होने पर रेस्क्यू टीमें पहले डूबे हुए इलाकों में पहुंच रही हैं, जिससे बड़े पैमाने पर तबाही नजर आ रही है। 12 दक्षिणी प्रांतों में 1.2 मिलियन से ज्यादा घर और 36 लाख लोग लगातार भारी बारिश से प्रभावित हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। वहीं बाढ़ और भूस्खलन की वजह से क्षतिग्रस्त सड़कों और संचार लाइनों के कारण कई इलाके बड़े पैमाने पर कट गए हैं। उत्तरी सुमात्रा प्रांत के मध्य टापानुली जिले और क्षेत्र के अन्य जिलों में राहत विमान की मदद से सहायता और आपूर्ति पहुंचाया जा रहा है। उत्तरी सुमात्रा पुलिस के प्रवक्ता के अनुसार सड़कों, बिजली और फोन नेटवर्क के पूरी तरह बंद होने के कारण बचाव दलों को बड़ी परेशानी हो रही है।

अमेरिका ने अफगानियों को वीजा जारी करने पर लगाई रोक, वॉशिंगटन डीसी में गोलीबारी के बाद ट्रंप सरकार का फैसला

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने वॉशिंगटन डीसी में गोलीबारी की घटना के बाद शुक्रवार से अप्रवासियों के खिलाफ जांच तेज और सघन कर दी है। साथ ही अमेरिकी विदेश विभाग ने अफगान नागरिकों के लिए वीजा जारी करने पर भी रोक लगा दी है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में लिखा कि 'राष्ट्रपति ट्रंप के विदेश विभाग ने अफगानिस्तान के सभी लोगों को वीजा जारी करने पर रोक लगा दी है। '

अमेरिकी अप्रवासन विभाग ने जारी किए निर्देश : विदेश विभाग के फैसले के बाद अमेरिकी सरकार ने देशभर में सभी शरण संबंधी फैसलों को भी तुरंत प्रभाव से रोक दिया है। बीते बुधवार को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में बेहद सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में हुई गोलीबारी के बाद ट्रंप प्रशासन ने यह सख्त कदम उठाया है। इस गोलीबारी में नेशनल गार्ड्स की एक महिला सैनिक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल है। इससे पहले अमेरिका के अप्रवासन विभाग के निदेशक जोसेफ एल्डो ने भी पुष्टि की थी कि अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अगले आदेश तक अफगानिस्तान के नागरिकों को वीजा जारी न करें। यह रोक तब तक जारी रहेगी, जब तक अमेरिकी सरकार अमेरिका में मौजूद हर अफगान नागरिक की पूरी तरह से सुरक्षा जांच नहीं कर लेती।

ग्रीन कार्ड धारकों के दस्तावेजों की भी जांच के आदेश : वॉशिंगटन डीसी में गोलीबारी के आरोपी की पहचान अफगान मूल के रहमानुल्ला लकनवाल के रूप में हुई थी, जो साल 2021 में अमेरिका आया था। रहमानुल्ला को इसी साल अमेरिका में शरण दी गई थी। गोलीबारी की घटना से नाराज राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रंप प्रशासन ने 19 देशों के ग्रीन कार्ड धारकों के दस्तावेजों की सघन जांच का भी आदेश दिया है। ट्रंप सरकार के इस फैसले से ग्रीन कार्ड धारकों में डर का माहौल पैदा हो गया है। जिन 19 देशों के ग्रीन कार्ड होल्डर्स के दस्तावेजों की जांच का फैसला किया गया है, उनमें अफगानिस्तान, बर्मा, चाड, कांगो गणतंत्र, इक्वेटोरियल गिनी, एरीट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यमन, बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेजुएला का नाम शामिल है।

ट्रंप के 'शांति सूत्रधार' डैन ड्रिस्कॉल: सबसे युवा आर्मी सेक्रेटरी, रूस-यूक्रेन प्रस्ताव के मुख्य वास्तुकार

वॉशिंगटन, एजेंसी। नॉर्थ कैरोलिना की ब्लू रिज पर्वत श्रृंखला अपनी धुंध भरी सुबहों, सरसराते चीड़ के जंगलों और धीमी रफ्तार से चलने वाले छोटे-छोटे कस्बों के लिए मशहूर है। इन्हीं शांत पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे-से शहर बैनर एल्क में एक लड़का पला-बढ़ा था। वह बोलने से ज्यादा देखने-समझने में विश्वास रखता था। पर उसके अंदर एक अनोखी स्पष्टता थी। जहां बाकी बच्चे खेल, फिल्मों या रोमांच की बातें करते थे, वहीं उसने बचपन से ही फौज में शामिल होकर देश की सेवा करने का सपना संजो लिया था। उसके शिक्षक अक्सर उसके धैर्य, सूझ-बूझ वाले सवालों और काम खत्म करने की तेजी से प्रभावित होते थे। आगे चलकर वह लड़का न सिर्फ सबसे कम उम्र का अमेरिका का आर्मी सेक्रेटरी बना, बल्कि वर्तमान में दुनिया की सबसे जटिल राजनीतिक और सैन्य चर्चा के केंद्र में भी है। ये हैं डैनियल 'डैन' पैट्रिक ड्रिस्कॉल, जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति का ड्रोन मैन भी कहा जाता है। फिलवक्त, वह कीव और मॉस्को के बीच ट्रंप के शांति प्रस्ताव के वास्तुकार बनने की वजह से सुर्खियों में हैं।

शुरुआत और परिवार : ड्रिस्कॉल का नॉर्थ कैरोलिना से गहरा नाता है, जहां दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ठिकानों में से एक फोर्ट ब्रैग समेत दस और मिलिट्री ठिकाने हैं। उन्होंने बैनर एल्क की पहाड़ियों में अपना बचपन बिताया। ड्रिस्कॉल अपने परिवार में तीसरी पीढ़ी के सैनिक हैं। उनके पिता वियतनाम युद्ध में शामिल थे, जबकि दादा द्वितीय विश्वयुद्ध में आर्मी डिकोडर रहे थे। उनकी मां गृहिणी थीं। ड्रिस्कॉल ने अपनी स्कूली शिक्षा वाटौगा हाई स्कूल से पूरी की। सेना में जल्दी शामिल होने की चाह थी, इसलिए उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना, चैपल हिल से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री सिर्फ तीन साल में हासिल कर ली। उन्होंने प्रतिष्ठित येल लॉ स्कूल से ज्यूरिस डॉक्टर की डिग्री भी हासिल की है। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने येल के वेटरंस लीगल सर्विसेज क्लिनिक में भी काम किया, सीनेट कमेटी ऑन वेटरंस अफेअर्स व नाइंथ सर्किट के चीफ जज एलेक्स कोजिंस्की के लिए इंटर्नशिप की। ड्रिस्कॉल ने अपनी हाई स्कूल की दोस्त, कैसी ड्रिस्कॉल से शादी की है, जो एक प्लास्टिक सर्जन हैं। इस दंपती के दो बच्चे, डैनियल जूनियर और लीला, हैं।

ट्रंप के भरोसेमंद : अपने ज्यादातर कॅरिअर में, डैन ड्रिस्कॉल ने निजी क्षेत्रों में काम किया। तकनीकी और साइबर सुरक्षा फर्मों में वरिष्ठ पेशेवर के तौर पर उन्होंने न केवल डाटा स्ट्रेटजी और कॉरपोरेट रिस्क असेसमेंट में काम किया, बल्कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन जैसे संवेदनशील विषयों को भी बड़े कौशल के साथ संभाला। वह 20 करोड़ डॉलर के वेंचर कैपिटल फंड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में भी काम कर चुके हैं। ड्रिस्कॉल सबसे नाजुक मुद्दों को भी बिना किसी हंगामे के शांत और असरदार ढंग से हल करने में माहिर हैं। उनकी इसी क्षमता ने राष्ट्रपति ट्रंप का भरोसा जीत लिया।

ट्रंप की पहल से रुकेगा एक और संघर्ष, अफ्रीकी देश अमेरिका में शांति समझौते पर करेंगे हस्ताक्षर

वॉशिंगटन, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक और संघर्ष विराम कराने जा रहे हैं। दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अफ्रीकी देश कांगो और रवांडा के राष्ट्रपति अमेरिका में 4 दिसंबर को मिलेंगे और शांति समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। दोनों देशों के बीच संघर्ष रुकवाने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन द्वारा कई महीनों से बातचीत की जा रही थी। कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स शीसेकेडी ने बताया कि कांगो किसी भी शांति समझौते पर तभी हस्ताक्षर करेगा, जब इस बात की गारंटी मिले की रवांडा की सरकार एम23 विद्रोही संगठन को कोई समर्थन नहीं देगी।

पूर्वी कांगो में छिड़ा है संघर्ष : कांगो के राष्ट्रपति ने 4 दिसंबर को रवांडा के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने की पुष्टि की है। वहीं रवांडा के राष्ट्रपति पॉल कागामे ने भी इसकी उम्मीद जताई। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि पूर्वी कांगो में शांति तभी संभव है, जब विवाद से सीधे तौर पर जुड़े लोग शांति के पक्ष में हों। पूर्वी कांगो में बीते कई महीनों से संघर्ष छिड़ा हुआ है। यह संघर्ष कांगो सरकार की सेना और 100 से ज्यादा विद्रोही संगठनों के बीच हो रहा है। इस विद्रोही संगठनों में सबसे ताकतवर एम23 समूह है, जिसे रवांडा की सरकार का समर्थन हासिल है। इस साल संघर्ष उस समय तेज हो गया, जब एम23 ने कांगो के दो बड़े शहरों गोमा और बुकावु पर कब्जा कर लिया।

रवांडा के सैनिक विद्रोही संगठन के साथ मिलकर पूर्वी कांगो में लड़ रहे : संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों का दावा है कि रवांडा की सेना के 3000-4000 जवान पूर्वा कांगो में मौजूद हैं और एम23 समूह के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। हालांकि रवांडा ने इन दावों को खारिज कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि यह संघर्ष पूर्वी कांगो की खनिज संपदा और कथित तौर पर अपने-अपने इलाकों की रक्षा के लिए है। इससे पहले जून में भी कांगो और रवांडा के विदेश मंत्रियों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें रवांडा के सैनिकों की पूर्वी कांगो से वापसी की बात पर सहमति बनी थी।

उल्लेखनीय है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वे आठ युद्ध रुकवा चुके हैं। इस सूची में कंबोडिया और थाईलैंड, सर्बिया, इस्राइल और ईरान, मिस्त्र और इथयोपिया, आर्मेनिया और अजरबैजान जैसे देशों का संघर्ष शामिल है। ट्रंप भारत और पाकिस्तान का संघर्ष रुकवाने का भी दावा करते हैं, लेकिन भारत ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है। बीते दिनों उन्होंने कहा कि आठ में से पांच युद्ध तो उन्होंने टैरिफ की धमकी देकर रुकवाए।

चिली में प्रवासियों के खिलाफ चल रहा अभियान, पलायन बढ़ते ही पेरू ने की सीमा पर आपातकाल के एलान की तैयारी

सैंटियागो, एजेंसी। पेरू के राष्ट्रपति जोस जेरी ने शुक्रवार को कहा कि उनकी सरकार देश की दक्षिणी सीमा पर आपातकाल का एलान करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार इलाके में ज्यादा सशस्त्र बलों को तैनात करेगी, क्योंकि बड़ी संख्या में वेनेजुएला के प्रवासी चिली से उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं, जहां अप्रवासी विरोधी भावनाएं बढ़ गई हैं। अपने देश में संकट से बचने या विदेश में बेहतर अवसरों की तलाश में लाखों प्रवासी लंबे समय से महाद्वीप और पेरू की सीमा पार कर चिली में नया जीवन बसर करने के लिए आ रहे हैं, जो लैटिन अमेरिका के सबसे स्थिर और समृद्ध देशों में से एक है। चिली में कानूनी दर्जा न रखने वाले बहुत से लोग हैं, इनमें ज्यादातर वेनेजुएला के हैं। ये लोग हाल के वर्षों में अपने देश की आर्थिक बर्बादी और सत्तावादी शासन से बचकर भागे हैं। हालांकि, अब ये दूसरी दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि चिली आव्रजन के खिलाफ अपना रुख सख्त करने की तैयारी कर रहा है। 14 दिसंबर को चिली में होने वाले राष्ट्रपति पद के दूसरे चरण के चुनाव में जीत के प्रबल दावेदार अति-रूढ़िवादी वकील जोस एंटोनियो कास्ट ने अपना अभियान वेनेजुएला से आने वाले अप्रवासियों और संगठित अपराध में वृद्धि को लेकर लोगों के डर के इर्द-गिर्द बुना है। उन्होंने पिछले हफ्ते पेरू से लगी चिली की रेगिस्तानी सीमा पर एक अभियान वीडियो फिल्माया, जिसमें बिना औपचारिक दर्जा वाले अप्रवासियों को चेतावनी दी गई है आपके पास अपनी इच्छा से चिली छोड़ने के लिए 111 दिन हैं। दिनों की यह मोहलत मौजूदा वामपंथी राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक के बाद नए प्रशासन के कार्यभार संभालने तक की है। उन्होंने कहा, 'अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम आपको रोकेंगे, आपको हिरासत में लेंगे, आपको निष्कासित कर देंगे। आप सिर्फ अपने तन पर पहने कपड़ों के साथ ही बाहर निकलेंगे।' जल्द ही पेरू का मीडिया उन प्रवासी परिवारों की तस्वीरों से भर गया जो चिली से पेरू की ओर भाग रहे थे, उनका सामान बैग और कचरे के थैलों में भरा हुआ था। कुछ ही दिनों के भीतर जारी ने सीमा नियंत्रण का निरीक्षण करने के लिए उसी क्षेत्र का दौरा किया और सुरक्षा अभियान को बढ़ावा देने के लिए सशस्त्र बल भेजे। चिली के उत्तरी सीमावर्ती कस्बों के निवासियों ने बढ़ती अराजकता की सूचना दी है, क्योंकि चिली छोड़कर पेरू में प्रवेश की अनुमति न मिलने पर भी लोगों की भीड़ अनिश्चितता में फंसी हुई है। शुक्रवार को जारी ने क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा करने के लिए अपने मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई। इस बात का कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है कि कास्ट की सामूहिक निर्वासन की धमकियों और आव्रजन वकीलों के अनुसार, 18.5 मिलियन की आबादी वाले दक्षिण अमेरिकी देश में विदेशी लोगों के प्रति बढ़ती नफरत की पृष्ठभूमि में कितने लोगों ने चिली छोड़ने का फैसला किया है। शुक्रवार को कास्ट ने एक नया वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने अप्रवासियों के लिए अपनी चेतावनी दोहराई और बोरिक से दखल देने का आग्रह किया।

ट्रम्प ने बाइडेन के 92% एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स रद्द किए: बोले- इन पर मशीन से दस्तखत थे, पूर्व राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं थी, इसलिए ये अवैध

वॉशिंगटन डीसी, एजेंसी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन के कार्यकाल में जारी किए गए 92% एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स को रद्द कर दिया है। ट्रम्प ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर इसकी जानकारी दी। ट्रम्प ने का दावा है कि ये सभी ऑटोपेन (मशीन से दस्तखत) से साइन किए गए थे, जो बिना बाइडेन की मंजूरी के अवैध हैं। इस कदम से बाइडेन के कई महत्वपूर्ण एक्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रभावित हो सकते हैं, जिनमें स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े नियम शामिल हैं। उन्होंने बाइडेन को 'स्लीपी (सुस्त) जो' और 'क्रुक्ड (चालाक) जो' कहते हुए धमकी दी कि अगर बाइडेन इन दस्तावेजों पर अपनी सहमति का दावा करेंगे तो उन पर 'झूठे बयान' के आरोप लगेंगे। ट्रम्प का यह फैसला व्हाइट हाउस के पास हुए नेशनल गार्ड्स पर हुए हमले के बाद आया है।

बाइडेन के कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर रद्द होने का खतरा : बाइडेन ने चार साल (2021-25) के कार्यकाल में कुल 162 एक्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए, साथ ही सैकड़ों ज्ञापन और नोटिस भी साइन किए थे। ट्रम्प ने पद संभालने के बाद जनवरी में ही करीब 80 बाइडेन-युग के ऑर्डर रद्द कर दिए थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण ऑर्डर अभी भी लागू हैं। इनमें से कुछ अब रद्द होने के खतरे में हैं।

एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14087: अमेरिका में प्रिस्क्रिप्शन दवाओं की कीमतें कम करने से जुड़ा। यह दवा कंपनियों पर नियंत्रण लगाता है, ताकि आम नागरिकों को सस्ती दवाएं मिल सकें।

एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14096: पर्यावरणीय न्याय पर केंद्रित, जो गरीब और अल्पसंख्यक समुदायों को पर्यावरण प्रदूषण से बचाने के उपाय करता है।

एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14110: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विकास और उपयोग पर सख्ती, जिसमें जोखिमों को कम करने और नैतिक उपयोग सुनिश्चित करने के नियम शामिल हैं। ट्रम्प के इस कदम से इन नीतियों पर असर पड़ सकता है, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि सभी दस्तावेजों के हस्ताक्षरों की वैधता साबित करना मुश्किल होगा। अभी यह साफ नहीं है कि कौन इन साइन की जांच करेगा।

क्या ट्रम्प बाइडेन के आदेशों को रद्द कर सकते हैं : कार्यकारी आदेश अमेरिकी राष्ट्रपति के जारी किए गए ऑर्डर होते हैं, जो संघीय एजेंसियों को कानूनों को लागू करने या नीतियां बनाने में मदद करते हैं। अमेरिकी कानून के अनुसार, कोई भी राष्ट्रपति अपने पिछले राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेशों को रद्द, संशोधित या अमान्य कर सकता है। हालांकि, इसकी अपनी सीमाएं भी हैं। खासकर क्षमादान, माफी और सजा में कमी के मामलों में, जिन्हें एक बार दिए जाने के बाद वापस नहीं लिया जा सकता। ट्रम्प का मुख्य दावा ऑटोपेन पर आधारित है। वे कहते हैं कि बाइडेन के 92% आदेश ऑटोपेन से हस्ताक्षरित थे, जो बिडेन की मंजूरी के बिना अवैध हैं। लेकिन कानूनी रूप से, ऑटोपेन का उपयोग पूरी तरह वैध है। जस्टिस डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ लीगल काउंसल ने 2005 में (जॉर्ज डब्ल्यू. बुश के समय) कहा था कि राष्ट्रपति को बिल या आदेश साइन करने के लिए व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर करने की जरूरत नहीं है, बशर्ते उनकी मंजूरी हो।

ट्रम्प ने बाइडेन पर झूठी गवाही का आरोप लगाने की धमकी दी : ट्रम्प ने बाइडेन पर परजरी (झूठी गवाही) का आरोप लगाने की धमकी दी है। उन्होंने कहा कि अगर बाइडेन ने कहा कि उन्होंने ऑटोपेन वाले दस्तावेदो को खुद अप्रूव किया था, तो उन पर परजरी के आरोप लगेंगे।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशकः सुरेश मौर्या द्वारा अष्ठ विनायक ओफ़्सेट एफपी, 149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास ,भाटेना) हो.सो अंजना सुरत गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक : सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/75100 (Subject to Surat jurisdiction)

Web site : www.krantisamay.com & epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

69 लाख पेंशनरों के लिए बढ़ी टेंशन, 8वें वेतन आयोग के टीओआर में पेंशन संशोधन पर उठे सवाल

2 दिसंबर को अधिकांश आशंकाएं हो सकती हैं दूर

नई दिल्ली

केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को लेकर चिंता गहराती जा रही है। हाल ही में जारी किए गए आयोग के टर्म्स ऑफ़ रेफरेंस (टीओआर) में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं के गायब होने या अस्पष्ट रहने को लेकर कर्मचारी यूनियनें विरोध जता रही हैं। इनका कहना है कि वेतन संशोधन, पेंशन ढांचा, एनपीएस/ओपीएस से जुड़े प्रावधान, डीए एरियर, दया नियुक्ति और ट्रेड यूनियन अधिकार जैसे मुद्दों पर स्पष्ट दिशा-निर्देश न होना सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करता है। इसे लेकर कर्मचारी यूनियनों ने सरकार को पत्र भी लिखे हैं।

इसी बीच, 1 दिसंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर कर्मचारियों और पेंशनरों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। सत्र प्रारंभ होने से पहले राज्यसभा में सांसद जावेद अली खान और रामजी लाल सुमन ने सरकार से सीधा प्रश्न किया है कि क्या सचमुच 8वें वेतन आयोग के टीओआर से पेंशन संशोधन को हटा दिया गया है। पहले के सभी वेतन आयोगों में पेंशन संशोधन स्पष्ट रूप से शामिल रहता था, लेकिन इस बार इसका

न होना बहस का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। पेंशनरों ने आशंका व्यक्त की है, कि कहीं इसे आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर करने पर विचार तो नहीं किया जा रहा है।

सांसदों ने सरकार से यह भी पूछा है, कि पेंशन संशोधन को प्रस्तावित नहीं करने के पीछे क्या कारण हैं?

कर्मचारी संगठनों का कहना है कि ऐसा कदम लाखों पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिरता को झटका दे सकता है। दूसरी ओर, महंगाई भत्ता (डीए) 50 फीसद पार कर चुका है और महंगाई दर भी ऊँची बनी हुई है।

ऐसे में डीए-डीआर को बेसिक पे में मर्ज करने की मांग भी तेज हो गई है। यूनियनों का कहना है कि यह कदम कर्मचारियों और पेंशनरों को तुरंत राहत दे सकता है। बताया गया है कि वित्त मंत्रालय 2 दिसंबर को इन मुद्दों पर आधिकारिक जवाब देने वाला है, जिससे कई आशंकाओं पर से पर्दा उठने की संभावना है।

69 लाख पेंशनरों पर सीधा असर

देश के लगभग 69 लाख पेंशनभोगी पेंशन संशोधन पर निर्भर रहते हैं, ताकि उनकी आय वर्तमान कर्मचारियों के अनुसार अद्यतन रह सके। यदि पेंशन संशोधन को वेतन आयोग के दायरे से बाहर किया गया, तो पुराने और नए पेंशनरों के बीच आय का फासला और बढ़ सकता है। यूनियनों ने टीओआर में शामिल अनफंडेड कॉस्ट ऑफ नन-कन्ट्रिब्यूट्री पेंशन स्कीम जैसी भाषा पर भी आपत्ति जताई है। उनके अनुसार, इससे संकेत मिलता है कि सरकार सामाजिक सुरक्षा की जगह वित्तीय बोझ को प्राथमिकता दे रही है।

दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश भारत से खरीद सकता हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल

नई दिल्ली

भारत और दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के बीच ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील और अन्य रक्षा सहयोग को लेकर चर्चा हो रही है। इंडोनेशिया ने भारत की स्वदेशी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में गहन दिलचस्पी दिखाई है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, यह डील अपने अंतिम चरण में है। भारत के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और इंडोनेशिया के रक्षामंत्री स्याफरी स्यामसुद्दीन के बीच नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता हुई। रक्षा मंत्री सिंह ने इंडोनेशिया के रक्षामंत्री को ब्रह्मोस मिसाइल का एक मॉडल भेंट किया।

भारत के प्रस्ताव पर डिफेंस इंडस्ट्री ज्वाइंट कॉर्पोरेशन कमिटी गठित करने पर सहमति बनी। इसका उद्देश्य रक्षा क्षेत्र से जुड़ी तकनीक हस्तांतरण, संयुक्त अनुसंधान व विकास और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग को बढ़ावा देना है।

इंडोनेशिया ने क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने में भारत को एक महत्वपूर्ण साझेदार बताया। आसियान के इंडो-पैसिफिक दृष्टिकोण और भारत की समुद्री पहल को समान मूल्यों वाला बताया गया।

समुद्री क्षेत्र जागरूकता, साइबर सुरक्षा, संयुक्त परिचालन क्षमता, रक्षा उद्योग सहयोग, पनडुब्बी तकनीक (विशेषकर स्कॉर्पीन श्रेणी कार्यक्रम), रक्षा चिकित्सा और फार्मा सहयोग पर विशेष जोर दिया गया। दोनों देशों ने तीनों सेनाओं के बीच बढ़ते संयुक्त अभियानों और अभ्यासों की सराहना की, जिनमें सुपर गरुड़ शील्ड, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, मिलन आदि शामिल हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रमों, सैन्य शिक्षा संस्थानों में आपसी विजिट और अधिकारी आदान-प्रदान में वृद्धि का निर्णय लिया गया, जिससे इंटरऑपरेबिलिटी और ज्ञान-साझेदारी बढ़ेगी।

महागठबंधन के विधायकों ने तेजस्वी को विधानमंडल में गठबंधन का नेता चुना

सोमवार से शुरू हो रहा विधानसभा का सत्र, सभी निर्वाचित विधायक लेंगे शपथ

पटना

बिहार में महागठबंधन के विधायकों ने राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के तेजस्वी यादव को सर्वसम्मति से राज्य विधानमंडल में गठबंधन का नेता चुन लिया। यह फैसला सोमवार से विधानसभा के शुरू हो रहे पांच दिवसीय सत्र से पहले आयोजित एक बैठक में लिया गया। इस सत्र के पहले दिन 243 सदस्यीय विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जाएगी। बैठक के बाद राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि तेजस्वी यादव को राज्य विधानमंडल में महागठबंधन का नेता चुना गया है। निश्चित रूप से वह विधानसभा में हमारी पार्टी के नेता होंगे।

कांग्रेस के विधान परिषद सदस्य (एमएलसी) और पार्टी की प्रदेश इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष समीर कुमार सिंह ने कहा कि तेजस्वी पर फैसला सर्वसम्मति से लिया गया है। हमारे पास पर्याप्त संख्या बल है और वह विपक्ष के नेता भी होंगे। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा, जिसमें एनडीए ने 202 सीट जीतकर बिहार में नीतीश सरकार की सत्ता बरकरार रखी।

सिंह ने कहा बैठक में विधानसभा के दोनों सदनों के सदस्यों ने चुनाव कराने के तरीके पर चिंता जताई। ये स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थे। पहले बिहार में आयोजित एसआईआर एक संदिग्ध प्रक्रिया बनी है।

दिसंबर में हो सकता है नीतीश सरकार का विस्तार, नए चेहरे बन सकते हैं मंत्री

अभी 9 मंत्री पद खाली, इनमें जेडीयू के 6, बीजेपी के 3 पद शामिल हैं

पटना

बिहार में एनडीए सरकार अगले महीने मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू और बीजेपी दोनों अपने खाली पड़े मंत्री पद भरने की तैयारी की जा रही हैं। इस विस्तार से सामाजिक और जातीय समीकरण साधने पर खास जोर रहेगा। वर्तमान में नीतीश कुमार कैबिनेट में कुल 9 मंत्री पद खाली हैं। इनमें जेडीयू के 6 पद, बीजेपी के 3 पद शामिल हैं।

वहीं सूत्रों की मानें तो जेडीयू मंत्रिमंडल में कुशवाहा और अति पिछड़े वर्ग के विधायकों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। माना जा रहा है कि पार्टी इस विस्तार के जरिए राज्य की जातीय और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखते हुए फैसला लेगी। सूत्रों का कहना है कि पार्टी मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका मिल सकता है। बिहार सरकार में सीएम समेत अधिकतम 36 मंत्री बन सकते हैं। एनडीए की सीट शेयरिंग के मुताबिक मंत्री पद तय हैं जिनमें बीजेपी के 17 जेडीयू के 15 मंत्री (सीएम सहित), एलजेपी (आर)- 2, हम-1 मंत्री और आरएलएम का 1 मंत्री है। इस हिसाब से जेडीयू और बीजेपी के खाते में अभी नए मंत्री शामिल होने की गुंजाइश है।

एसआईआर प्रक्रिया को लेकर आयोग के रवैये से लोग चिंतित, कुछ तो गड़बड़ है

पहले भी हुआ है एसआईआर, सचिन पायलट ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना

नई दिल्ली

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन पायलट ने मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर निर्वाचन आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि इस प्रक्रिया को लेकर आयोग के रवैये से लोगों के मन में चिंता है। पायलट ने आरोप लगाया कि फील्ड स्टाफ पर अनावश्यक दबाव और जल्दबाजी में समयसीमा तय करने से पता चलता है कि प्रक्रिया में कुछ तो गड़बड़ है।

राजस्थान के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने कहा कि एसआईआर देश में पहले भी कई बार हुआ है। लेकिन कोई चर्चा नहीं होती थी, लोगों के मन में कोई आशंका नहीं रहती थी। पहली बार निर्वाचन आयोग का जो रवैया रहा है। उससे लोगों के मन में चिंता है। पायलट ने आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार में लोगों के नाम काटे गए। कई राज्यों में लोग तनाव में हैं, और कुछ तो इस दबाव के कारण आत्महत्या भी कर रहे हैं। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि कुछ गड़बड़ हो रही है।

सचिन पायलट ने कहा कि निर्वाचन आयोग को निष्पक्ष संस्था के रूप में काम करना चाहिए क्योंकि मतदाता सूची के शुद्धिकरण का काम निर्वाचन आयोग का है, किसी राजनीतिक दल का नहीं।

पायलट ने कहा कि कांग्रेस देश भर में अभियान चला रही है ताकि यह तय किया जा सके कि कोई भी नागरिक अपने मतदान के अधिकार से वंचित न हो।

उन्होंने कहा कि हम यह तय करना चाहते हैं कि गरीब लोग, दलित, आदिवासी और बुजुर्ग जागरुकता की कमी के कारण या किसी के द्वारा उनका नाम हटाने की मंशा के कारण मतदान के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित न हों।

दिल्ली बम धमाका: तीन डॉक्टर समेत मौलवी को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

अब तक एनआईए ने इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है

नई दिल्ली

दिल्ली की एक अदालत ने लाल किला के पास हुए बस विस्फोट मामले में गिरफ्तार तीन डॉक्टरों और एक मौलवी को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। इन सभी आरोपियों को शनिवार को प्रधान एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चांदना के समक्ष पेश किया गया था, जिन्होंने चारों को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। अब तक एनआईए ने इस मामले में सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा भंडाफोड़ किए गए एक 'सफेदपोश' आतंकी मॉड्यूल से जुड़े हैं।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एनआईए ने कहा कि एजेंसी आत्मघाती बम विस्फोट के सिलसिले में सुरागों की तलाश कर रही है और इस हमले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए संबंधित पुलिस बलों के साथ समन्वय में कई राज्यों में तलाशी अभियान चला रही है। 10 नवंबर को लाल किले के बाहर विस्फोटकों से लदी कार में विस्फोट हुआ था, जिसे डॉ. उमर चला रहा था। एजेंसी ने इससे पहले इसी मामले में दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इन आरोपियों से पूछताछ जारी है और एनआईए इस पूरे आतंकी मॉड्यूल की गहन जांच कर रही है। हमले की जांच केंद्र गृह मंत्रालय द्वारा एनआईए को सौंपी गई थी। इसके बाद से एजेंसी कई राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर इस मॉड्यूल से जुड़े हर सदस्य का पता लगाने और उसे न्याय के कठघरे में लाने की दिशा में काम कर रही है। एनआईए का कहना है कि वह इस साजिश की पूरी परतें खोलने और इसके मास्टरमाइंड तक पहुंचने के लिए कोशिश कर रही है।

अब डॉक्टर के लिखने पर ही मिलेगा कफ सिरप, सरकार ने बढ़ाई सख्ती; निगरानी होगी कड़ी

नई दिल्ली

राजस्थान और मध्य प्रदेश में संदिग्ध कफ सिरप पीने से कई बच्चों की मौत के बाद केंद्र और राज्य सरकारों ने कफ सिरप की बिक्री पर सख्त नियम लागू कर दिए हैं। नए आदेश के तहत अब डॉक्टर के लिखे पर्चे के बिना कोई भी मेडिकल स्टोर कफ सिरप नहीं बेच सकेगा। साथ ही, हर बिक्री का विवरण एक रजिस्टर में अनिवार्यतः दर्ज करना होगा, जिसमें खरीदार और पर्चा लिखने वाले डॉक्टर का ब्यौरा भी दर्ज करना होगा।

सरकारी आदेश के बाद सभी मेडिकल स्टोर और निजी अस्पतालों जहां प्रतिदिन बड़ी मात्रा में कफ सिरप की बिक्री होती है, पर विशेष निगरानी रखी जा सकेगी। अनुमान है कि ऐसा करने से न केबल कफ सिरप की अवैध बिक्री पर रोक लग सकेगी, बल्कि अवैध, मिलावटी या निम्न गुणवत्ता वाली दवाओं की बिक्री भी रोकी जा सकेगी। सरकार का कहना है कि इन नियमों से मिलावटी दवाओं की बिक्री, फर्जी कंपनियों का कारोबार तथा कफ सिरप के दुरुपयोग पर रोक लगेगी, जबकि मरीजों को केवल सुरक्षित और डॉक्टर द्वारा निर्धारित दवा ही उपलब्ध कराई जा सकेगी।

गौरतलब है कि साधारण खांसी-जुखाम होने पर सामान्यतः लोग बिना डॉक्टर को दिखाए और पर्चा लिखवाए ही मेडिकल दुकान से कफ सिरप खरीद कर उसका इस्तेमाल करते रहे हैं। बड़ी तादाद में कफ सिरप का इस्तेमाल नशे के लिए भी किए जाने के आरोप लगते रहे हैं। बढ़ती कफ सिरप की मांग के चलते मुनाफाखोर कथित कंपनियां और मेडिकल दुकान वाले निम्न गुवात्ता वाले कफ सिरप भी बेंच रहे थे, जिस कारण मासूमों की मौत का मामला भी सामने आ चुका है। ऐसे में नए नियमों के बाद अब केवल वैध पर्चे पर ही कफ सिरप मिल

सकेगा, जिससे बिक्री पर नियंत्रण आसान होगा।

यहां बताते चलें कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिलों में स्थानीय ब्रांड के कफ सिरप पीने से करीब एक दर्जन बच्चों की मौत हुई थी। सिरप में डाइ-इथिलीन ग्लाइकोल (डीईजी) और इथिलीन ग्लाइकोल (ईजी) जैसे खतरनाक तत्व पाए जाने की आशंका जताई गई थी। इसके मद्देनज़र औषधि नियंत्रण विभाग ने सभी राज्यों को कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

कट्टरपंथियों की खतरनाक साजिश को बेनकाब करेंगी 12 पीड़ित युवतियां

दिल्ली में लव जिहाद की शिकार लड़कियां डिटेल में बयां करेंगी अपनी कहानियां

नई दिल्ली

भारत समेत कई देश कट्टरपंथ की साजिश का शिकार हैं। डेमोग्राफिक्स को बदलने की साजिशें रची जा रही है। चिंता की बात यह है कि इस मामले में डॉक्टर और इंजीनियर जैसे बहुत पढ़े-लिखे लोग भी इस साजिश में शामिल हैं। इसका उदाहरण लाल किले के पास हुआ आतंकवादी हमला है। इन सबको देखते हुए देश में पहली बार ऐसा इवेंट हो रहा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लव जिहाद की शिकार लड़कियां अपनी कहानियां डिटेल में बताएंगी और इसके तरीकों का खुलासा करेंगी। इस खास इवेंट में दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और विश्व हिंदू परिषद के स्टेट प्रेसिडेंट कपिल खन्ना खास तौर पर शामिल होंगे। उनके साथ लव जिहाद की शिकार लड़कियों को बचाने वाले लोग भी होंगे।

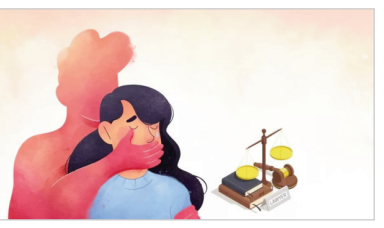

विहिप दिल्ली के मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने बताया कि 12 लड़कियां, खासकर केरल की, जो लव जिहाद की शिकार हुई हैं, अपनी कहानियां बताएंगी, ताकि हर कोई इस साजिश के बारे में जान सके और समय रहते अपने बेटियों को बचा सके। दिल्ली एनसीआर की चार और पीड़ित भी इस इवेंट में मौजूद रहेंगी। केरल भारत में लव जिहाद का सेंटर है, जहां हजारों लड़कियों को बहला-फुसलाकर इस्लाम कबूल करवाया गया है और फिर उन्हें इस्लामिक देशों में ट्रैफिकिंग के लिए भेज दिया गया।

संक्षिप्त समाचार

अब सीनियर वकील किसी भी बेंच के सामने मामलों का नहीं करेंगे मौखिक उल्लेख

सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल मामलों की लिस्टिंग प्रक्रिया पर किया सर्कुलर जारी

नई दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर वकीलों को किसी भी बेंच के सामने मामलों का मौखिक उल्लेख करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने स्थगन और तत्काल मामलों की लिस्टिंग के लिए प्रक्रिया तय करने वाला एक सर्कुलर जारी किया है। इसके मुताबिक जमानत या जमानत रद्द करने, मृत्युदंड, हेबियस कॉर्पस, विध्वंस या अंतरिम राहत से संबंधित सभी नए मामले अगले दो कार्य दिवसों में लिस्ट किए जाएंगे। इसमें साफ कहा गया है कि किसी भी कोर्ट के समक्ष मौखिक उल्लेख के लिए किसी सीनियर वकील को इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके बजाय, युवा जूनियर वकीलों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सर्कुलर में कहा गया है कि अगर कोई मामला अत्यंत तत्काल प्रकृति का हो, जैसे अग्रिम जमानत, मृत्युदंड, हेबियस कॉर्पस, बेदखली या विध्वंस से जुड़ा और तय तारीख पर लिस्टिंग का इंतजार न कर सके, तो प्रोफॉर्मा के साथ एक पत्र अधिकारी को सुबह 10:30 बजे से पहले देना होगा। अनावश्यक स्थगनों को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से भी कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि मामले का स्थगन केवल परिवार में मृत्यु, अधिवक्ता या पक्षकार-व्यक्ति की चिकित्सा, स्वास्थ्य स्थिति या कोर्ट को संतुष्ट करने वाले अन्य वास्तविक कारणों के मामलों में ही स्वीकार किया जाएगा। यह कदम न्यायिक प्रक्रिया को ज्यादा सुव्यवस्थित और पारदर्शी बनाने की दिशा में उठाया गया है, जिससे तत्काल मामलों का निपटारा तेजी से हो सके।

दुनिया का अनूठा मुक्तिधाम, 12 राशियों के 12 मंडप

राशियों के आधार पर अंतिम संस्कार

इटावा उत्तर प्रदेश के इटावा में दुनिया का सबसे अनूठा मुक्तिधाम बना है। यहां पर अंतिम संस्कार वाराणसी के मनिकर्निका घाट से लाई गई अग्नि के माध्यम से की जाती है। इस मुक्तिधाम का निर्माण 2017 में किया गया था। यहां पर जो भी शव अंतिम संस्कार के लिए लाये जाते हैं। उनका नाम ओर राशियों के अनुसार अंतिम संस्कार किया जाता है। इसके लिए 12 मंडप बनाए गए हैं। हर मंडप में चार-चार चबूतरे तैयार किए गए हैं। हर मंडप में नाम और राशि का उल्लेख किया गया है। अंतिम संस्कार के लिए जो शव आते हैं। उनका अंतिम संस्कार उनकी ही राशि के मंडप में होता है। इस मुक्तिधाम में लकड़ी मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। परिजन जो दान में देना चाहते हैं। वह दान करते हैं। वृंदावन के पागल बाबा आश्रम से जुड़े हुए श्याम सुंदर चौरसिया का कहना है। वह हर पूर्णिमा को वृंदावन जाते हैं। 2014 में उनके छोटे बेटे और बड़ी बहू की मौत एक दुर्घटना में हो गई थी। उसके बाद उन्होंने कारोबार त्याग कर समाज सेवा के काम शुरू कर दिया। उन्होंने इटावा में एक यज्ञशाला का निर्माण कराया है। वहीं रहते हैं, और नियमित पूजा पाठ करते हैं। 2017 में 12 राशियों के हिसाब से मुक्तिधाम तैयार किया। बनारस से वह अग्नि लेकर आए थे। जिसे उन्होंने हवन कुंड में हमेशा जलाकर रखा है।

दिल्ली में हवा 'बहुत खराब' श्रेणी में, आईएमडी ने किया अलर्ट

नई दिल्ली

दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' श्रेणी में है, हालांकि प्रदूषण स्तर में मामूली गिरावट दर्ज की गई है। औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 305 पर रहा। अधिकारियों के मुताबिक अनुकूल हवाओं की दिशा एवं गति तथा पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं में आई कमी से प्रदूषण के स्तर में यह गिरावट दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 'स्काईमेट वेदर' के उपाध्यक्ष ने बताया कि अगले कुछ दिनों तक वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में रह सकता है। हवा की गति तेज रहने की संभावना के कारण, एक्यूआई कम से कम अगले दो दिनों तक 'गंभीर' श्रेणी में नहीं जाएगा। इस बीच दिल्ली में लगातार औसत एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया है। सीपीसीबी के मुताबिक शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51-100 को 'संतोषजनक', 101-200 को 'मध्यम', 201-300 को 'खराब', 301-400 को 'बहुत खराब' और 401-500 को 'गंभीर' माना जाता है। सीपीसीबी के समीर ऐप से पता चला है कि दिल्ली के 38 सक्रिय निगरानी स्टेशनों में से किसी ने भी शनिवार को एक्यूआई को 'गंभीर' श्रेणी दर्ज नहीं की, जबकि एक दिन पहले आठ स्टेशनों ने 'गंभीर' श्रेणी में प्रदर्शित की थी। वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली ने दिल्ली के लिए पूर्वानुमान लगाया है कि आगामी सप्ताह में एक्यूआई 'बहुत खराब' श्रेणी में रहेगा। शनिवार को उत्तर-पश्चिम से 15 किमी प्रति घंटे की गति से सतही हवाएं चलीं।